Working Paper No. 180

UTTARAKHAND ANDOLAN UTTARAKAHNDION KI NAZAR MEIN

A.K. SINGH
P.S. GARIA

UTE OF DEVELOPMENT STUDIES
Sector 'O', Aliganj Housing Scheme
LUCKNOW 226 024

2002

Working Paper No.180

UTTARAKHAND ANDOLAN UTTARAKAHDION KI NAZAR MEIN
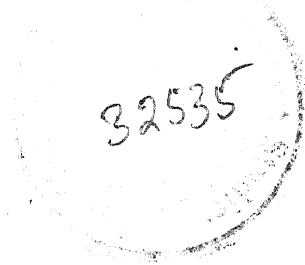
A. K. SINGH
P.S. GARIA

GIRI INSTITUTE OF DEVELOPMENT STUDIES
Sector 'O' Aliganj Housing Scheme
LUCKNOW 226 024
2002

उत्तराखण्ड आन्दोलन उत्तराखण्डियों की नज़र में+

अजीत कुमार सिंह
तथा
प्रताप सिंह गढ़िया *

स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात् हुये अनेक क्षेत्रवादी व पृथक राज्यवादी आन्दोलनों में उत्तराखण्ड आन्दोलन एक विशेष स्थान रखता है। अन्य आन्दोलनों की तुलना में यह एक मूलभूत रूप से शांति प्रिय आन्दोलन था, जिसको क्षेत्र के लगभग सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त था। इस व्यापक जनसमर्थन को देख कर प्रमुख राजनैतिक दल भी इस आन्दोलन से जुडे और स्वयं राज्य सरकार ने एक से अधिक बार उत्तराखण्ड को एक पृथक राज्य बनाने का प्रस्ताव विधान मण्डल से पारित कराके केन्द्र सरकार को भेजा। लगभग एक दशक की उहापोह के पश्चात केन्द्र सरकार को भी इस मांग को स्वीकार करना पड़ा। अन्ततः 9 नवम्बर, 2000 को इस आन्दोलन की परिणिति एक नये व पृथक राज्य के रूप में हुयी, जब उत्तरांचल नाम से भारतीय संघ के सत्ताइसवें राज्य का गठन हुआ। प्रस्तुत अध्ययन में उत्तराखण्ड आन्दोलन को जन्म देने वाले कारणों, उसके जनाधार और उससे सम्बन्धित विभिन्न पक्षों का विश्लेषण किया गया है। हालांकि नवीन राज्य का नाम उत्तराचल रखा गया है, जो स्वयं में विवाद का एक मुद्दा रहा है, हमने इस आन्दोलन को उत्तराखण्ड आन्दोलन के नाम से ही सम्बोधित किया है क्योंकि इसी नाम को लेकर यह आन्दोलन चला है और दीर्घकाल से यह क्षेत्र इसी नाम से जाना जाता रहा है।

अध्ययन के उद्देश्य

संक्षेप में इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित पक्षों पर जानकारी प्राप्त करना है :,

1. उत्तराखण्ड आन्दोलन को जन्म एवं बढावा देने वाले क्या कारण हैं?
2. उत्तराखण्ड की समस्याओं एवं विकास प्रक्रिया के बारे में क्षेत्रवासियों के क्या विचार है?
3. उत्तराखण्ड के विकास की वैकल्पिक नीतियों के सम्बन्ध में क्षेत्रवासियों के क्या विचार हैं?
4. उत्तराखण्ड आन्दोलन में विभिन्न सामाजिक वर्गों की क्या भूमिका रही है?
5. उत्तराखण्ड आन्दोलन में विभिन्न राजनैतिक दलों की क्या भूमिका रही है?
6. नये उत्तरांचल राज्य के समक्ष क्या प्रमुख राजनैतिक एवं आर्थिक चुनौतियां हैं?

अध्ययन की पद्धति

हमने उपरोक्त प्रश्नों पर उत्तराखण्ड में निवास करने वाले बुद्धिजीवियों, नेताओं व वरिष्ठ नागरिकों के विचारों को जानने का प्रयास किया है। इसके लिये एक सुविचारित प्रश्नावली तैयार की गयी। इस प्रश्नावली को क्षेत्र के 100 से अधिक चयनित व्यक्तियों को डाक के माध्यम से भेजा गया, जिनमें समाज के विभिन्न वर्गों यथा अध्यापक, वकील, पत्रकार, राजनैतिक दलों के पदाधिकारी, विधायक, जिला व क्षेत्र

+ यह अध्ययन भारत–डच वैकल्पिक विकास प्रोजेक्ट (इडपैड) के द्वारा पोषित "भारत में क्षेत्रीय द्वैतवाद, विकास प्रक्रिया तथा राज्य की नीतियां" शोध अध्ययन पर आधारित है।

* क्रमशः प्रोफेसर एवं फैलो, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ।

पंचायतों के अध्यक्ष व आन्दोलन में सक्रिय प्रमुख व्यक्ति सम्मिलित थे। साथ ही यह भी ध्यान रखा गया कि उत्तराखण्ड के विभिन्न जिलों का भी सही प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। हमको 50 व्यक्तियों से प्रश्नावली के उत्तर प्राप्त हुये। इन उत्तरों का सारणीयन करके उनका विश्लेषण किया गया।

यह सर्वेक्षण वर्ष 2000 में अगस्त से अक्टूबर के दौरान किया गया, जो उत्तराखण्ड राज्य के गठन के पूर्व की स्थिति को दर्शाता है। प्रस्तुत अध्ययन में उत्तराखण्ड आन्दोलन को उत्तराखण्डियों की दृष्टि से देखने का प्रयास किया गया है। हमारे विचार में इस अध्ययन से एक विश्वसनीय और क्षेत्रवासियों के विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाला चित्र उभरकर आया है, जो उत्तराखण्ड आन्दोलन के विभिन्न पक्षों पर रोशनी डालता है। उत्तरों का विश्लेषण व निष्कर्ष हमारे अपने हैं।

अपने अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों को प्रस्तुत करने से पहले यह समीचीन होगा कि उत्तराखण्ड क्षेत्र व उत्तराखण्ड आन्दोलन की पृष्ठभूमि पर एक त्वरित दृष्टिपात कर लिया जाय।

उत्तराखण्ड की भौगोलिक, आर्थिक व प्रशासनिक पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में मध्य हिमालय में पड़ने वाले कुमायूं तथा गढ़वाल मण्डल के आठ जिलों (अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, पौढ़ी, उत्तरकाशी, देहरादून व टेहरी) को उत्तराखण्ड के नाम से जाना जाता रहा है। नब्बे के दशक में इन जिलों का पुनर्गठन कर चार नये जिलों (उधमसिंह नगर, रूद्र प्रयाग, चम्पावत व बागेश्वर) का सृजन किया गया। उत्तराखण्ड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 51,124 वर्ग किलोमीटर है, जो उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 17 प्रतिशत है। 1991 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की जनसंख्या 59.3 लाख थी, जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 4.3 प्रतिशत थी।

उत्तराखण्ड की एक विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति है जो उसको उत्तर प्रदेश के सपाट मैदान से पृथक करती है। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण इस क्षेत्र में पर्याप्त भौगोलिक विभिन्नतायें पायी जाती हैं। सामान्यतः इस क्षेत्र को पांच भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता है, यथा तराई व भाभर क्षेत्र, शिवालिक पहाड़ियाँ, लघु हिमालय, वृहत् हिमालय तथा ट्रांस हिमालय क्षेत्र (पंत, 1999)। यह क्षेत्र प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है तथा वानस्पतिक विविधता से पूर्ण है। क्षेत्र का लगभग दो–तिहाई हिस्सा वनों से आच्छादित है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल यहीं है।

जनसख्या का घनत्व, जो 1991 की जनगणना के अनुसार 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, अपेक्षाकृत कम है। क्षेत्र की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण अंचलों में निवास करती है। शिक्षा के क्षेत्र में यह क्षेत्र अग्रणी रहा है। 1991 में उत्तराखण्ड की साक्षरता दर 59.58 प्रतिशत थी, जबकि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर मात्र 41.60 प्रतिशत थी।

उत्तराखण्डवासियों की एक विशिष्ट आनुवांशिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषायी अस्मिता रही है, जो उसको उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों के लोगों से पृथक करती है। यह विशिष्टता क्षेत्रवासियों को एक अलग पहचान देती है और उनको क्षेत्रीय व सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पिरोती है, जो क्षेत्र में स्थित जातीय भिन्नताओं से ऊपर है। उत्तराखण्ड की जनसंख्या का सामाजिक ढांचा भी उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से बहुत अलग है। यहां लगभग 78 प्रतिशत लोग उच्च जाति (मुख्यतः ब्राहमण एवं ठाकुरों के हैं तथा केवल 2 प्रतिशत पिछड़ी जातियों के हैं) (वाल्दिया, 1996, पृ0 8)। क्षेत्र के 16.7 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति तथा 3.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के हैं।

इसी प्रकार उत्तराखण्ड क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की भी अपनी विशिष्टतायें हैं। लगभग 36 प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक रूप से क्रियाशील है। स्त्रियों की कार्यसहभागिता दर 25.62 प्रतिशत है जो मैदानी भागों से काफी अधिक है। लगभग दो–तिहाई श्रमिक कृषि क्षेत्र में संलग्न है। अधिकांश जोते सीमान्त जोतों की श्रेणी में ही आती है। औद्योगिक रूप से यह क्षेत्र पिछड़ा रहा है। रोजगार की सम्भावनाओं के अभाव में बडी संख्या में श्रमशक्ति का पलायन सुदूर क्षेत्रों को होता रहा है (बोरा, 1996)। इसी कारण उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था को **मनीआर्डर इकानॉमी** की संज्ञा व्यापक रूप से दी जाती रही है।

ब्रिटिश शासनकाल से ही प्रशासनिक व कानूनी दृष्टि से उत्तराखण्ड की व्यवस्था मैदानी भागों से कुछ हट कर रही है। इस क्षेत्र की विकास की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर 1969 में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया गया। इसी कडी में 1973 में एक पृथक पर्वतीय विकास विभाग स्थापित किया गया और एक पूर्णकालिक सचिव की नियुक्ति की गयी।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल से ही पर्वतीय क्षेत्र को, पूर्वी उत्तर प्रदेश व बुन्देलखण्ड सहित, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया था, जिनके विकास के लिये विशेष प्रयोजनों की आवश्यकता थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना के काल से पर्वतीय क्षेत्र के योजनागत परिव्यय को पृथक रूप से आवंटित किया जाता रहा है। केन्द्रीय योजना आयोग के स्तर पर भी इसी समय, यह निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को लगभग उतनी विशेष सहायता धनराशि दी जाय जो हिमाचल प्रदेश को दी जाती है, जिसकी जनसंख्या व क्षेत्रफल उत्तराखण्ड से तुलनीय है। तालिका संख्या–1 में उत्तराखण्ड क्षेत्र की योजनाओं पर किये गये व्यय तथा उसके लिये प्राप्त केन्द्रीय सहायता को प्रदर्शित किया गया है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में उत्तराखण्ड का आयोजनागत व्यय उत्तर प्रदेश के आयोजनागत व्यय का लगभग 7 प्रतिशत था। आगामी योजनाओं में यह प्रतिशत लगभग 10 हो गया तथा नवीं योजना के दौरान लगभग 12 प्रतिशत तक पहुँच गया। इस प्रकार अपनी जनसंख्या के अनुपात की तुलना में, जो 5 प्रतिशत से कम रहा है, उत्तराखण्ड को आंवटित योजना परिव्यय का अनुपात लगभग दो–ढाई गुना अधिक रहा है। केन्द्र से उत्तराखण्ड क्षेत्र को मिलने वाली धनराशि भी निरन्तर बढ़ती रही है।

तालिका संख्या–1
उत्तराखण्ड व उत्तर प्रदेश में योजनागत व्यय

(करोड़ रू0)

क्रसं0	योजना अवधि		कुल व्यय		उत्तराखण्ड के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता
			उत्तर प्रदेश	उत्तराखण्ड	
1.	पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974–79)		2909.23	204.02 (7.01)	104.00
2.	छटी पंचवर्षीय योजना (1980–85)		6594.29	658.67 (9.99)	350.00
3.	सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90)		11948.72	1213.10 (10.15)	679.19
4.	वार्षिक योजना (1990–92)		7772.00	614.89 (7.91)	364.02
5.	आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97)		21679.82	2105.00 (9.71)	1005.00
6.	नवीं पंचवर्षीय योजना	(1997–98)	5666.70	567.92 (10.02)	225.00
		(1998–99)	6363.94	722.35 (11.35)	362.41
		(1999–2000)	6568.87	792.68 (12.07)	457.86

स्रोत : उत्तर प्रदेश सरकार, नियोजन विभाग, पंचवर्षीय योजनाओं से संकलित
टिप्पणी : कोष्ठक में दी गयी संख्यायें उत्तर प्रदेश से प्रतिशत दिखाती हैं।

इन प्रयासों के फलस्वरूप उत्तराखण्ड में सामाजिक व आर्थिक अवस्थापना के स्तर में नियोजन काल में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। उल्लेखनीय है कि सामाजिक व आर्थिक विकास के अनेक सूचकांकों में पर्वतीय क्षेत्र की स्थिति सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की स्थिति की तुलना में कही अधिक संतोषप्रद है, जैसा कि तालिका संख्या–2 में देखा जा सकता है। यहां इस बात का उल्लेख भी आवश्यक हो जाता है कि पर्वतीय क्षेत्र के विभिन्न अंचलों में काफी आर्थिक विषमतायें पायी जाती हैं। साथ ही ये प्रयास उत्तराखण्डवासियों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफल रहे। विकास का मुद्‌दा उत्तराखण्ड आन्दोलन में एक महत्वपूर्ण मुद्‌दे के रूप में उभर कर आया (नौटियाल 1994, वल्दिया 1996, मेहता 1997)।

तालिका संख्या–2

उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति सम्बन्धी कुछ प्रमुख संकेतक

क्र.सं0	संकेतक	उत्तराखण्ड	उत्तर प्रदेश
1.	जनसख्या का घनत्व (1991)	116	473
2.	कुल जनसंख्या में कर्मकरों का प्रतिशत (1991)	36.4	29.7
3.	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कर्मकरों से प्रतिशत (1991)	64.6	72.2
4.	फसल सघनता (1997,98)	161.7	148.7
5.	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल से प्रतिशत (1997–98)	34.9	68.6
6.	प्रति हेक्टेयर सकल बोये गये क्षेत्रफल पर कुल उर्वरक वितरण (किलोग्राम) (1997–98)	89.4	117.6
7.	प्रति व्यक्ति कृषि उपज का सकल मूल्य (रू0) (प्रचलित भावों पर) (1996–97)	2463	2872
8.	प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन का सकल मूल्य (रू0) (1990–91)	785	1527
9.	प्रति लाख जनसख्या पर पंजीकृत कारखानों में लगे व्यक्तियों की संख्या (1990–91)	721	485
10.	कुल उपमुक्त विद्युत में से कृषि में उपमुक्त विद्युत का प्रतिशत (1997–98)	14.4	41.5
11.	प्रति व्यक्ति विद्युत उपमोग की मात्रा (कि0वा0घं0) (1997–98)	240.0	163.1
12.	ऋण जमा अनुपात (मार्च 1999)	21.5	27.2
13.	प्रति लाख जनसंख्या पर जूनियर बेसिक स्कूल (संख्या)(1998–99)	139	57
14.	प्रति लाख जनसख्या पर सीनियर बेसिक स्कूल (सख्या)(1998–99)	31	13
15.	प्रति लाख जनसंख्या पर हायर सेकेण्डरी स्कूल (संख्या)(1998–99)	18	5
16.	प्रति लाख जनसंख्या पर जूनियर बेसिक विद्यार्थियों की संख्या (1998–99)	11671	8011
17.	प्रति लाख जनसंख्या पर सीनियर बेसिक विद्यार्थियों की संख्या (1999–99)	3411	1881
18.	प्रति लाख जनसंख्या पर हायर सेकेण्डरी विद्यार्थियों की संख्या (1998–99)	6409	3449
19.	प्रति लाख जनसख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की सख्या (11.1.1998)	11.02	3.40
20.	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शय्याओं की सख्या (11.1.1998)	107.76	46.55
21.	प्रति हजार आबाद्‌ मजरों पर नल द्वारा पेयजल सुविधा युक्त मजरों की संख्या (1998–99)	982	997
22.	प्रति लाख जनसंख्या पर लोक नि0 वि0 के अधीन पक्की सड़कों की लम्बाई (कि0 मी0) (1998–99)	207.00	63.01
23.	प्रति हजार वर्ग कि0 मी0 क्षेत्रफल पर लोक नि0 वि0 की पक्की सड़कों की लम्बाई (कि0 मी0) (1998–99)	280.34	353
24.	विद्युतीकरण ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत (1998–99)	80.45	78.54

स्रोत : अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, सांख्यकीय डायरी, उत्तर प्रदेश, 2000, लखनऊ।

हालांकि उत्तराखण्ड क्षेत्र के विकास के लिये एक पृथक विभाग बनाया गया और उसके लिये पृथक से नियोजन धनराशि आवंटित की गयी और विशेष केन्द्रीय सहायता भी दी गयी, फिर भी विकास प्रक्रिया के सम्बन्ध में एक असंतोष की भावना बनी रही। बुद्धिजीवियों और अर्थशास्त्रियों ने भी इस असंतोष को अपने अध्ययनों में व्यक्त किया।

मेहता के विचार में :

"संक्षेप में, उत्तराखण्ड की विकास योजनाओं की मुख्य समस्या यह नहीं रही है कि पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं से सामान्यतः लोग अवगत नहीं थे या केन्द्रीय व प्रदेशीय नियोजनकर्त्ताओं में प्रतिबद्धता की कमी थी, वरन् यह कि इस क्षेत्र के नियोजन की सोच और उसके कार्यान्वन में एक समन्वित और क्षेत्र विशिष्ट उपागम का अभाव रहा है।"

(मेहता, 1991, पृ031)

एक अन्य जानकार के विचार में : 'क्योंकि पिछले चार दशकों की विकास प्रक्रियायें मध्य हिमालय के उत्तराखण्ड सम्भाग की सामाजिक परिस्थितियों पर कोई देखने लायक प्रभाव छोड़ने में सामान्यतः असफल रही हैं, अतः प्रशासन की रणनीति में ऐसा परिवर्तन आवश्यक है जो विकास की पद्धति और विभिन्न क्षेत्रों के कार्यक्रमों के स्वरूप में, सत्ता और उत्तरदायित्व का उत्तराखण्डवासियों के प्रति विकेन्द्रीकरण कर, बदलाव ला सके।'

(वाल्दिया, 1996, पृ07)

विभिन्न राजनैतिक दलों के घोषणा पत्रों, प्रत्यावेदनों लेखों आदि में क्षेत्र के आर्थिक पिछडेपन एवं विकास की असंतुलित और दोषपूर्ण प्रक्रिया को पृथक राज्य के औचित्य के रूप में प्रमुखता से रखा गया है (देखें नौटियाल, 1994 में संकलित दस्तावेज़)।

उत्तराखण्ड आन्दोलन : एक संक्षिप्त परिचय

उत्तराखण्ड आन्दोलन की एक दीर्घकालीन पृष्ठभूमि है (देखें नौटियाल, 1994, पृ0 241–260)। आजादी के पूर्व भी सन् 1946 में हल्द्वानी नगर में बद्रीदत्त पाण्डे की अध्यक्षता में हुए एक सम्मेलन में पर्वतीय क्षेत्र के लिये पृथक प्रशासनिक ईकाई बनाने की मांग की थी।

देश की आजादी के समय से ही उत्तराखण्ड के आठ जनपदों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग उठने लगी थी। राज्यों के पुर्नगठन के लिये बनाये गये आयेाग के सदस्य के0 एम0 पाणिकर ने सुझाव दिया था कि उत्तर प्रदेश के हिमालय क्षेत्र के विकास के लिये अलग राज्य बनाया जाना आवश्यक है, लेकिन तत्कालीन कांग्रेसी सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। सन् 1952 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, पी0 सी0 जोशी ने पृथक पर्वतीय राज्य की मांग उठायी। सन् 1954 में विधान परिषद सदस्य इन्द्र सिंह नयाल ने कुमायूं की परिस्थितियों को देखते हुए अलग प्रबन्ध व्यवस्था की मांग की। पांचवे व छठे दशक में पृथक उत्तराखण्ड राज्य के पक्ष में उठाये गये स्वर मद ही रहे और इस समय की राज्य व केन्द्र सरकारों ने इन स्वरों को अनसुना किया।

सन् 1967 में रामनगर में एक सम्मेलन हुआ जिसमें पर्वतीय राज्य परिषद नामक संगठन की स्थापना की गयी। सन् 1966–67 में कम्युनिस्ट पार्टी ने भी पृथक राज्य का समर्थन किया। सन् 1973 में दिल्ली में विशाल सम्मेलन हुआ जिसमें पर्वतीय राज्य परिषद का नाम बदलकर **उत्तराखण्ड राज्य परिषद** कर दिया गया। सन् 1974 में पौड़ी के सांसद प्रताप सिंह नेगी ने संसद में उत्तराखण्ड के लिए प्रस्ताव रखा। सन् 1976 में उत्तराखण्ड युवा मोर्चा नामक सगठन की स्थापना की गयी। 1978 में इस मोर्चे ने बद्रीनाथ से बोट क्लब, नई दिल्ली की यात्रा की तथा महिलाओं सहित 73 लोग दिल्ली तिहाड़ जेल भेजे गये।

सत्तर के दशक से उत्तराखण्ड के समर्थन में उठाये गये प्रयत्न तेज होने लगे। राज्य सरकार ने इस क्षेत्र की समस्याओं पर अधिक ध्यान देने के लिये 1973 में एक पृथक पर्वतीय विकास विभाग का गठन किया, जिसका उल्लेख पहले किया गया है। जुलाई 1979 में मसूरी मे पर्वतीय जन विकास सम्मेलन किया गया, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलो के लोगों ने भाग लिया। सम्मेलन में व्यक्त विचारों के आधार पर उत्तराखण्ड क्रांन्ति दल का गठन हुआ। अस्सी के दशक में पृथक राज्य के आन्दोलनों ने जोर पकड़ा तथा कई संगठन बने जिनमें उत्तराखण्ड पर्वतीय राज्य परिषद, उत्तराखण्ड संघर्ष वाहिनी, उत्तराखण्ड क्रान्ति दल, उत्तराखण्ड प्रगतिशील युवा मंच प्रमुखतः उल्लेखनीय हैं। इन संगठनों ने पृथक अथवा संयुक्त रूप से आन्दोलन को आगे बढ़ाया। 1989 को ये विभिन्न संगठन उत्तराखण्ड संयुक्त संघर्ष समिति के झण्डे के नीचे एक साथ आये।

पृथक उत्तराखण्ड की मांग के जनाधार को बढ़ते हुये देखकर विभिन्न राजनीतिक दल भी इसके समर्थन में आगे आये। 1991 के अप्रैल–जून के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने केन्द्रीय घोषणापत्र में उत्तरांचल राज्य को बनाने के प्रति अपनी कटिबद्धता प्रकट की। इसका उसको राजनीतिक लाभ भी मिला और उत्तराखण्ड की संसद की चारो सीटों और विधान सभा की 19 में से 15 सीटों पर वह विजयी रही। 1991 में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने पृथक उत्तरांचल राज्य बनाने का प्रस्ताव विधान सभा से पारित कराकर केन्द्र सरकार को भेजा। 1993 में मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी की मिलीजुली सरकार ने पुनः पृथक उत्तराखण्ड राज्य का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को प्रेषित किया और पृथक उत्तराखण्ड के निर्माण के हेतु व्यापक विचार के लिये रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।

इसी बीच जिस बात ने समस्त उत्तराखण्ड को विचलित कर दिया वह थी मुलायम सिंह सरकार के द्वारा 8 अगस्त, 1994 को शिक्षा व नौकरी के क्षेत्र में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा। उत्तराखण्ड की सामाजिक संरचना में, जहां उच्च जातियों का बाहुल्य है और पिछड़े वर्ग के केवल 2–3 प्रतिशत ही लोग रहते हैं, इस घोषणा का विरोध स्वाभाविक था। इस आरक्षण घोषणा से समस्त समाज विशेषकर युवावर्ग अपने भविष्य के प्रति बहुत ही आशंकित हो गया, क्योंकि शिक्षा और नौकरी की सम्भावनाओं पर इससे काले बादल से छा गये। प्रदेश सरकार ने आरक्षण विरोधी आन्दोलन का राजनीतिक हल न ढूंढ कर दमनकारी नीति अपनाई, जिसने आन्दोलन को और तूल दिया। 1 सितम्बर को खटीमा में तथा 2 सितम्बर को मसूरी में आन्दोलनकारियों पर पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें अनेक लोग मारे गये। 2 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित रैली में भाग लेने के लिये जा रही जनता को पुलिस द्वारा मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर रोका गया। पुलिस के द्वारा बसों को आग लगायी गयी और गोलियां चलाई गयी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग हताहत हुये। महिलाओं के साथ भी अमानुषिक व्यवहार किया गया। इन घटनाओं को समाचार माध्यमों ने खूब प्रचारित किया। परिणामस्वरूप समूचे उत्तराखण्ड में आक्रोश फैल गया और आन्दोलन की एक अभूतपूर्व लहर उठी, जिसमें सभी वर्गो ने विशेषकर महिलाओं व युवाओं ने बढ़–चढ़ कर भाग लिया। इस प्रकार खटीमा, मसूरी और मुजफ्फरनगर की घटनाओं ने उत्तराखण्ड आन्दोलन को एक नया ही स्वरूप और आधार दे दिया।

क्षेत्र की जनभावनाओं को देखते हुए केन्द्र की जनता दल सरकार के प्रधानमंत्री देवगौड़ा को 15 अगस्त, 1996 को उत्तराखण्ड राज्य बनाने की घोषणा करनी पडी। लेकिन पृथक उत्तराखण्ड के सपने साकार होने का अवसर तभी सामनें आया जब भाजपा सरकार केन्द्र में शासनारूढ हुयी और उसने तीन नये राज्यों (छत्तीसगढ, झारखण्ड व उत्तराखण्ड) को बनाने का प्रस्ताव संसद से पारित किया और 8 नवम्बर सन् 2000 की मध्यरात्रि से उत्तराखण्ड भारतीय संघ के नक्शे पर एक पृथक राज्य के रूप में अवतरित हुआ।

आगामी पृष्ठों में हमने उत्तराखण्ड आन्दोलन से जुड़े पक्षों पर विचार किया है। जैसे, उत्तराखण्ड राज्य को उत्तर प्रदेश से अलग करने की आवश्यकता क्यों पडी ? उत्तराखण्ड के विकास के लिए उत्तर प्रदेश में एक अलग विभाग होने पर भी उत्तराखण्ड के विकास में कौन सी बाधायें आयी ? उत्तराखण्ड की मुख्य समस्यायें क्या थी ? उत्तराखण्ड आन्दोलन को किस राजनैतिक दल, सक्रिय सगठन, जाति/समुदाय व किस क्षेत्र से अधिक बल मिला ? तथा उत्तराखण्ड आन्दोलन कब एक जन आन्दोलन के रुप में उभरा ? जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है हमारा अध्ययन उत्तराखण्ड क्षेत्र के 50 बुद्धिजीवियों के उत्तरों पर आधारित है।

<u>उत्तरदाताओं की विशेषतायें</u>

तालिका संख्या–3 में उत्तरदाताओं की विशेषताओं को दर्शाया गया है। लगभग 46.0 प्रतिशत उत्तरदाता 45 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के, 38.0 प्रतिशत उत्तरदाता 25 से 45 आयु वर्ग के तथा 14.0 प्रतिशत उत्तरदाता 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। मात्र 1 उत्तरदाता 25 वर्ष

से कम आयु का है। अधिकांश उत्तरदाता उच्च जाति के हैं, जिनका उत्तराखण्ड में वर्चस्व है। लगभग 48.0 प्रतिशत उत्तरदाता ब्राह्म्ण और लगभग 36.0 प्रतिशत उत्तरदाता राजपूत जाति के है। शेष 16 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य जातियों के हैं।

तालिका संख्या –3
उत्तरदाताओं की विशेषताएं

विशेषताएं	कुमायूं	गढ़वाल	कुल	प्रतिशत
1. उत्तरदाताओं का आयु वर्ग				
25 वर्ष से कम	-	1	1	2
25–45 वर्ष	10	9	19	38
45–60 वर्ष	16	7	23	46
60 वर्ष और अधिक	3	4	7	14
कुल	**29**	**21**	**50**	**100**
2. उत्तरदाताओं की जाति				
ब्राहमण	15	9	24	48
राजपूत	9	9	18	36
अनुसूचित जाति	1	-	1	2
अनुसूचित जनजाति	1	-	1	2
अन्य	3	3	6	12
कुल	**29**	**21**	**50**	**100**
3. उत्तरदाताओं का शिक्षा स्तर				
प्राथमिक	1	-	1	2
जूनियर हाई स्कूल व हाई स्कूल	4	1	5	10
इण्टर	1	-	1	2
स्नातक व उससे ऊपर	23	20	43	86
कुल	**29**	**21**	**50**	**100**

यह उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड में शिक्षा का प्रसार पहले से ही अधिक रहा है। यह उत्तरदाताओं के शैक्षिक स्तर में परिलक्षित होता है। लगभग 86.0 प्रतिशत उत्तरदाता स्नातक व स्नातक से अधिक शिक्षा प्राप्त किये हुये है। मात्र एक उत्तरदाता केवल पांचवी कक्षा तक शिक्षा ग्रहण किये हुये है तथा शेष 12.0 प्रतिशत उत्तरदाता जूनियर हाई स्कूल से इण्टर तक की शिक्षा ग्रहण किये हुए हैं।

<u>उत्तरदाताओं की राजनैतिक सम्बद्धता</u>

लगभग 40.0 प्रतिशत उत्तरदाता प्रत्यक्ष रुप से राजनैतिक दलों से जुड़े हुये हैं (तालिका संख्या 4)। राजनैतिक दलों से जुड़े उत्तदाताओं में 40.0 प्रतिशत कांग्रेस से तथा 25–25 प्रतिशत उत्तरदाता क्रमशः भारतीय जनता पार्टी व उत्तराखण्ड क्रान्ति दल से जुड़े है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी व समाजवादी पार्टी से एक–एक उत्तरदाता जुड़ा है। लगभग 30 प्रतिशत उत्तरदाता वर्तमान समय में क्षेत्रीय व जिला अध्यक्ष, महासचिव, सचिव तथा कार्यकारणी सदस्य/प्रवक्ता आदि के रुप में पदधारण किए हुए है। 10 प्रतिशत उत्तरदाता क्षेत्र या जिला पंचायत के पदाधिकारी अथवा सदस्य हैं तथा 1 उत्तरदाता वर्तमान में विधायक है (तालिका संख्या 5)।

तालिका संख्या –4

उत्तरदाताओं का राजनैतिक दलों से सम्बद्धता

सम्बद्धता की प्रकृति	कुमायूं		गढ़वाल		कुल	प्रतिशत	
1. किसी राजनैतिक दल से सम्बद्ध है ?							
(1) हॉ	10		10		20	40	
(2) नहीं	19		11		30	60	
यदि हॉ, तो किस दल में							
(1) बी0 जे0 पी0	4		1		5	10	
(2) कांग्रेस	3		5		8	16	
(3) यू0 के0 डी0	3		2		5	10	
(4) सी0 पी0 आई0	-		1		1	2	
(5) स0 पा0	-		1		1	2	
विभिन्न दलों में भूतकाल व वर्तमान में पद धारण की स्थिति	भूतकाल	वर्तमान	भूतकाल	वर्तमान	भूतकाल	वर्तमान	भूतकाल
(1) अध्यक्ष	2	2	3	1	5	3	-
(2) उपाध्यक्ष	-	2	-	-	-	2	-
(3) महासचिव	1	-	-	2	1	2	-
(4) सचिव	-	2	2	1	2	3	-
(5) अन्य	3	3	4	3	7	6	-
कुल पद धारक	**6**	**9**	**9**	**7**	**15**	**16**	**-**
गैर पद धारक	**4**	**1**	**1**	**3**	**5**	**4**	**-**

तालिका संख्या –5

विभिन्न संस्थाओं में चुने सदस्य के रूप में कार्य करने की स्थिति

पद	कुमायूं		गढ़वाल		कुल	
	भूतकाल	वर्तमान	भूतकाल	वर्तमान	वर्तमान	भूतकाल
ब्लाक प्रमुख/सदस्य	2	2	-	1	2	3
अध्यक्ष/जिला परिषद सदस्य	-	1	3	1	3	2
विधायक	-	-	-	1	-	1
योग	2	3	3	3	5	6

इस प्रकार, हमारे उत्तरदाता उत्तराखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों, वर्गों व राजनैतिक विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके उत्तरों के आधार पर उत्तराखण्ड आन्दोलन के विभिन्न आयामों का एक विश्वसनीय विश्लेषण किया जा सकता है।

उत्तराखण्ड आन्दोलन में उत्तरदाताओं की भूमिका

राजनैतिक दलों द्वारा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए पृथक राज्य की मांग यदा–कदा की जाती रही। लेकिन जब उत्तराखण्ड आन्दोलन ने एक जन आन्दोलन का रुप ले लिया तो उत्तराखण्ड में विद्यमान कर्मचारी संगठन, महिला संगठन, छात्र संगठन, भूतपूर्व सैनिक संगठन व क्षेत्र में कार्यरत ऐच्छिक संगठन पृथक राज्य निर्माण हेतु आन्दोलन में कूद पड़े। इस आन्दोलन ने कई नये संगठनों को भी जन्म दिया।

हमारे अध्ययन के लगभग 52.0 प्रतिशत उत्तरदाता, उत्तराखण्ड आन्दोलन में सक्रिय संगठनों के पदाधिकारी अथवा सदस्य के रुप में आन्दोलन में भागीदार रहे हैं (तालिका संख्या 6)। शेष उत्तरदाताओं ने सक्रिय संगठनों के माध्यम से उत्तराखण्ड आन्दोलन में कोई भूमिका नहीं निभाई। जो 26 उत्तरदाता उत्तराखण्ड आन्दोलन में सक्रिय संगठनों से जुड़े थे, उनमें से 12 उत्तरदाताओं ने बताया कि वे जिस संगठन से जुड़े थे उसका किसी भी राजनैतिक दल से जुड़ाव नहीं था। शेष 14 में से 8 उत्तरदाताओं ने अपने संगठन को कांग्रेस से, 3 ने उत्तराखण्ड क्रान्तिदल से, 2 ने समाजवादी पार्टी से तथा 1 ने भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी से जुड़े होने की बात स्वीकारी है।

यह उत्तरदाता प्रमुखतः उत्तरांचल संघर्ष समिति से जुड़े हुये है, जो विभिन्न राजनैतिक दलों का एक संयुक्त संगठन है। अन्य उत्तरदाता जिन गैर राजनैतिक संगठनों से जुड़े हैं उनमें उत्तराखण्ड जन–संघर्षवाहिनी, लोक चेतना मंच, उत्तराखण्ड वन पंचायत संघर्ष समिति, बार एसोसियेशन, उत्तराखण्ड दलित पिछड़ा मंच उल्लेखनीय है।

तालिका संख्या –6
उत्तराखण्ड आन्दोलन में उत्तरदाताओं की भूमिका

भूमिका की प्रकृति	कुमायूं	गढ़वाल	कुल	प्रतिशत
1. क्या आपने सक्रिय संगठन के माध्यम से आन्दोलन में भूमिका निभाई है ?				
(i)हाँ	14	12	26	52
(ii)नहीं	15	9	24	48
2. यदि हाँ, तो धारित पद				
(i) अध्यक्ष	3	7	10	20
(ii) उपाध्यक्ष	2	-	2	4
(iii) महासचिव	3	2	5	10
(iv) अन्य	6	3	9	18
कुल	**14**	**12**	**26**	**52**
3. क्या ये संगठन किसी राजनैतिक दल से सम्बद्ध है?				
(i) यू0 कं0 डी0	9	3	12	24
(ii) कांग्रेस	2	1	3	6
(iii) सी0 पी0 आई0	3	5	8	16
(iv) स0 पा0	-	1	1	2
(v) नहीं	-	2	2	4
कुल	**14**	**12**	**26**	**52**
4. संस्था का नाम				
(i) उत्तरांचल संघर्ष समिति	5	6	11	22
(ii) उत्तरांचल जन संघर्ष वाहिनी	1	-	1	2
(iii) लोक चेतना मंच	1	-	1	2
(iv) उत्तराखण्ड पंचायत संघर्ष समिति	1	-	1	2
(v) बार संघ	1	-	1	2
(vi) उत्तराखण्ड दलित पिछड़ा मंच	-	1	1	2
(vii) अन्य	5	5	10	20
कुल	**14**	**12**	**26**	**52**

5. आन्दोलन में सक्रिय रहने का समय				
(i) 2 वर्ष से कम	4	1	5	10
(ii) 2–5 वर्ष	6	2	8	16
(iii) 5–10 वर्ष	7	6	13	26
(iv) 10–15 वर्ष	3	4	7	14
(v) 15 वर्ष से अधिक	9	8	17	34
कुल	**29**	**21**	**50**	**100**
6. हड़तालों मे भागीदारी				
(i) सतत	15	13	28	56
(ii) कभी–कभी	4	5	9	18
(iii) बहुत कम	10	3	13	26
कुल	**29**	**21**	**50**	**100**

लगभग 50 प्रतिशत उत्तरदाता 10वर्ष से अधिक समय से उत्तराखण्ड आन्दोलन में संघर्षशील रहे हैं (तालिका संख्या–6)। 26.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 5 से 10 वर्ष तथा 16.0 प्रतिशत ने 2 से 5 वर्ष तक उत्तराखण्ड आन्दोलन में सक्रीय रहने की बात को स्वीकारा है। मात्र 10.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पिछले 2 वर्षों से आन्दोलन में सक्रिय रहने की बात स्वीकारी है। इससे अधिकांश उत्तरदाताओं की उत्तराखण्ड आन्दोलन के प्रति कटिबद्धता प्रगट होती है। यह इससे भी स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने अलग राज्य निर्माण के लिए समय–समय पर होने वाली हड़तालों में सतत् रूप से भाग लिया है।

विकास प्रक्रिया के सम्बन्ध में विचार

उत्तरदाताओं से हमने यह जानने का प्रयास भी किया कि क्या उत्तर प्रदेश जैसे बडे राज्य का हिस्सा होने से उत्तराखण्ड के विकास में कठिनाइयाँ आयी है? तो इस सम्बन्ध में 66.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पूर्ण सहमति तथा लगभग 28.0 प्रतिशत ने आंशिक सहमति व्यक्त की है। केवल 6.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस पर अपनी असहमति व्यक्त की है। कुमायूँ व गढ़वाल मण्डल में रहने वाले उत्तरदाताओं ने लगभग समान विचार व्यक्त किये हैं।

उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में उत्तराखण्ड से मात्र 21 विधान सभा सदस्य व देश की संसद में मात्र 4 सदस्य होने से राजनैतिक दृष्टि से उत्तराखण्ड का कोई विशेष महत्व नहीं था। इसकी वजह से उत्तराखण्ड का विकास नकारात्मक रूप से प्रभावित होने के सम्बन्ध में 48.0 प्रतिशत उत्तरदाता पूर्णतया सहमत तथा 36.0 प्रतिशत उत्तरदाता कुछ सीमा तक सहमत पाये गये। केवल 16.0 प्रतिशत उत्तरदाता इस बात से असहमत पाये गये है।

उत्तराखण्ड के विकास को अवरूद्ध करने वाले कारणों में उसको मिलने वाली धनराशि का अपर्याप्त होना माना जाता रहा है। इस बात का 56.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने दृढ़तापूर्वक समर्थन किया तथा 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कुछ हद तक समर्थन किया। जबकि शेष 14.0 प्रतिशत उत्तरदाता उत्तराखण्ड को वितरित किये गये धन को काफी समझते हैं।

साधारणतया लोगों की यह शिकायत रही है कि उत्तराखण्ड का विकास स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं व आंकाक्षाओं के अनुसार नहीं किया जा रहा है। हमारे अध्ययन के लगभग 74.0 प्रतिशत उत्तरदाता पूर्णतया व दृढ़तापूर्वक इस बात का समर्थन करते है जबकि शेष उत्तरदाता कुछ सीमा तक इस बात के समर्थक है। किसी भी उत्तरदाता ने इस बात पर असहमति व्यक्त नहीं की है।

तालिका संख्या–7
उत्तराखण्ड की विकास प्रकिया के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के विचार

उत्तरदाताओं के विचार	कुमायूं	गढ़वाल	कुल	प्रतिशत
1. क्या उ0 प्र0 राज्य का एक भाग होने से उत्तराखण्ड का विकास बाधित हुआ है ?				
(1) पूर्णतया सहमत	18	15	33	66
(2) आंशिक रूप से सहमत	9	5	14	28
(3) असहमत	2	1	3	6
कुल	**29**	**21**	**50**	**10**
2. क्या निर्णय लेने की प्रकिया में भूमिका होने से उत्तराखण्ड विकास बाधित हुआ है ?				
(1) पूर्णतया सहमत	11	13	24	48
(2) आंशिक रूप से सहमत	14	4	18	36
(3) असहमत	4	4	8	16
कुल	**29**	**21**	**50**	**100**
3. उत्तराखण्ड को जो धनराशि आवंटित की जाती है वह अपर्याप्त है ?				
(1) पूर्णतया सहमत	17	11	28	56
(2) आंशिक रूप से सहमत	8	7	15	30
(3) असहमत	4	3	7	14
कुल	**29**	**21**	**50**	**100**
विकास स्थानीय आवश्यकताओं व आकांक्षाओं के अनुसार नहीं किया गया				
(1) पूर्णतया सहमत	19	18	37	74
(2) आंशिक रूप से सहमत	10	3	13	26
(3) असहमत	-	-	-	-
कुल	**29**	**21**	**50**	**100**

इस विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तराखण्डी पूर्व विकास प्रक्रिया से असंतुष्ट रहे हैं और मानते हैं कि इस क्षेत्र पर्याप्त धन.संसाधन उपलब्ध नहीं कराये गये और विकास प्रक्रिया स्थानीय आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं हुई।

<u>संसाधनों के दोहन व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के विचार</u>

उत्तराखण्ड वासियों की यह सामान्य शिकायत रही है कि उपलब्ध भूमि, वन, खनिज व जल आदि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप न करके उत्तराखण्ड से बाहर के लोगों व क्षेत्रों के हित में किया जाता रहा है। हमारे अध्ययन में भी यह बात उभर कर आयी है। 62.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस बात का पूर्ण समर्थन किया तथा 26.0 प्रतिशत उत्तरदाता कुछ हद तक इसका समर्थन करते हैं। केवल 12.0 प्रतिशत उत्तरदाता इस बात से सहमत नहीं है (तालिका संख्या 8)।

तालिका संख्या–8
संसाधनों के विदोहन व भ्रष्ट्राचार के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के विचार

उत्तरदाताओं के विचार	कुमायूं	गढ़वाल	कुल	प्रतिशत
1. इस क्षेत्र के संसाधनों का विदोहन अन्य लोगों ने किया है।				
(1) पूर्णतया सहमत	18	13	31	62
(2) आंशिक रूप से सहमत	8	5	13	26
(3) असहमत	3	3	6	12
2. विकास प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की मौजूदगी				
(1) पूर्णतया सहमत	21	20	41	82
(2) आंशिक रूप से सहमत	8	1	9	18
(3) असहमत	-	-	-	-
3. स्थानीय आवश्कताओं के प्रति कर्मचारियों की उदासीनता				
(1) पूर्णतया सहमत	11	14	25	50
(2) आशिक रूप से सहमत	14	6	20	40
(3) असहमत	4	1	5	10

जो धनराशि क्षेत्र को उपलब्ध भी करायी गयी, उसका सदुपयोग नहीं हो पाया, जिसने व्यापक असंतोष को जन्म दिया। भ्रष्टाचार ने उत्तराखण्ड आन्दोलन को हवा देने में एक मुख्य भूमिका निभाई है। अधिकतर निर्माण कार्यों को ठेकेदारी प्रथा से कराने के कारण वैधानिक व अवैधानिक कमीशनखोरी का जोर रहा और कार्यों की गुणवत्ता निम्न रही। हमारे अध्ययन के लगभग 82.0 प्रतिशत उत्तरदाता भ्रष्टाचार की व्यापकता से पूर्णतया सहमत हैं। शेष 18 प्रतिशत उत्तरदाता भी इस बात की आंशिक पुष्टि करते हैं। उल्लेखनीय है कि किसी भी उत्तरदाता ने विकास की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार व्याप्त होने से इंकार नहीं किया।

स्थानीय समस्याओं के प्रति कर्मचारियों की उदासीनता भी जन आक्रोश का एक कारण रही है। उत्तराखण्ड के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उत्तराखण्ड में सरकारी कर्मचारियो को अक्सर चार 'पी' के आधार पर नियुक्त किया जाता रहा है, अर्थात् प्रोबेशन, प्रमोशन, पनिष्मेंट तथा पेंशन। जब किसी की प्रदेश सरकार में नौकरी लगती थी उसको प्रोबेशन काल में उत्तराखण्ड भेजा जाता था या जिस अधिकारी की पदोन्नति होती थी उसको उत्तराखण्ड भेजा जाता था। यदि कोई सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो या उसकी चरित्र पंजिका खराब हो तो उस कर्मचारी या अधिकारी को भी दण्ड के तौर पर उत्तराखण्ड भेजा जाता था। इसके अलावा उत्तराखण्ड के जिलों में सीमान्त भत्ता, पर्वतीय भत्ता मिलने के प्रलोभन में भी कई कर्मचारी व अधिकारी पर्वतीय क्षेत्र मे नियुक्त होना चाहते थे। 50.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कर्मचारियों की उदासीनता पर पूर्ण सहमति व्यक्त की तथा लगभग 41.0 प्रतिशत ने आंशिक सहमति व्यक्त की। केवल 9.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस बात पर असहमति व्यक्त की है।

उत्तराखण्ड की मुख्य समस्याओं के प्रति विचार

हमारे द्वारा उत्तराखण्ड की मुख्य समस्याओं के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के विचार आमंत्रित किये गये। उनके उत्तरों के अनुसार जो समस्यायें उभर कर आयी हैं उनको तालिका संख्या 9 में दर्शाया गया है। उत्तरदाताओं के अनुसार जो सबसे बड़ी समस्या उत्तराखण्ड में विद्यमान है वह है आय और रोजगार के अवसरों की कमी जिसका उल्लेख लगभग आधे उत्तरदाताओं ने किया है। दूसरी मुख्य समस्या अवस्थापना के सीमित विकास की बतायी गयी, जो क्षेत्र में पेयजल, विजली, सड़कों, यातायात के साधनों व दूरसंचार साधनों की कमी की ओर

इंगित करती है। इस बात की पुष्टि 40.0 प्रतिशत लोगों ने की। तीसरी मुख्य समस्या क्षेत्र विशेष में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के अवैध व अवैज्ञानिक दोहन की बतायी गयी। जहाँ खनन क्षेत्र में चूना पत्थर, खड़िया (सोप स्टोन) खनन व नदी के बालू व बजरी का अवैध खनन करके क्षेत्र में खनन माफिया पैदा हो गये है वहीं दूसरी ओर पर्वतीय क्षेत्र में पाये जाने वाले विभिन्न जड़ी,बूटियों व इमारती लकड़ियों का अवैध व्यापार वन माफियाओं द्वारा किया जाता रहा है जबकि स्थानीय लोगों को इसका तनिक भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। इस बात का समर्थन हमारे अध्ययन के 28.0 प्रतिशत उत्तरदाता करते है। कुमायूँ मण्डल के उत्तरदाताओं ने इस समस्या पर अधिक बल दिया।

तालिका संख्या –9
उत्तराखण्ड की मुख्य समस्याओं के सम्बन्ध में विचार

1. उत्तराखण्ड की मुख्य समस्यायें	कुमायूँ	गढ़वाल	कुल	प्रतिशत
(1) आय व रोजगार के अवसरों की कमी	16	7	23	46
(2) अवस्थापना विकास की कमी	13	7	20	40
(3) स्थानीय संसाधनों का अनुचित विदोहन	10	4	14	28
(4) लघु एवं कुटीर उद्योगों की न्यूनता	8	4	12	24
(5) व्यावसायिक, तकनीकी शिक्षा व प्रशिक्षण की कमी	6	2	8	16
(6) नवयुवकों का पलायन	5	8	13	26
(7) बागवानी व प्रोसेसिंग ईकाइयों का विकास न होना	2	3	5	10
(8) ईंधन व चारे की समस्या	-	2	2	4
(9) कृषि समस्यायें जैसे लघु जोत, सिंचाई व भूमि संरक्षण	4	4	8	16
(10) साहसी उद्यमियों की कमी	1	2	3	6
(11) भ्रष्टाचार	2	3	5	10
(12) नशाखोरी	4	1	5	10

हमारे उत्तरदाताओं में से लगभग एक चौथाई ने नव युवकों के पलायन को मुख्य समस्या बताया। क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों के उपलब्ध न होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र के नवयुवक प्रवास करने को विवश होते है। कुमायूँ मण्डल की तुलना में गढ़वाल मण्डल के उत्तरदाताओं ने प्रवास की समस्या का अधिक उल्लेख किया।

औद्योगिक अवस्थापनाओं का अभाव, कच्चे माल की न्यूनता व साहसी लोगों व पूँजी के अभाव के कारण उत्तराखण्ड में बड़े उद्योगों की सम्भावनाये सीमित है। परन्तु रोजगार व पर्यावरण की दृष्टि से व पर्याप्त कच्चे माल की उपलब्धता को देखते हुए उत्तराखण्ड में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। लेकिन इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया हमारे अध्ययन के लगभग एक चौथाई उत्तरदाता उत्तराखण्ड में लघु एवं कुटीर उद्योगों की न्यूनता को एक प्रमुख समस्या मानते हैं।

हमारे उत्तरदाताओं ने जिन अन्य समस्याओं का उल्लेख किया है वे हैं व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा की कमी, बागवानी व फलों की प्रासेसिगं इकाईयों का अधिक विकास न होना, कृषि जोत का छोटा व बिखरा होना, सिंचाई के साधनों की कमी, भूमि कटाव व धंसाव की समस्या, भ्रष्टाचार व नशाखोरी, साहसी उद्यमियों की कमी तथा ईधन व चारे की समस्या।

उत्तराखण्ड के वैकल्पिक विकास योजनाओं के सम्बन्ध में सुझाव

जहाँ हमारे अध्ययन के उत्तरदाताओं ने उत्तराखण्ड की अनेक समस्याओं से हमें अवगत कराया है, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखण्ड विकास रणनीति के लिए अनेक वैकल्पिक सुझाव भी प्रस्तुत किये हैं, जिन्हें तालिका संख्या–10 में दर्शाया गया है। उत्तराखण्ड में जहाँ प्रकृति

ने कई रमणीय स्थल प्रदान किये हैं, वहीं देवभूमि कहे जाने के कारण बद्रीनाथ, हरिद्वार, पंच प्रयाग व बागनाथ जैसे तीर्थ स्थल उत्तराखण्ड में विद्यमान हैं। प्राकृतिक सौन्दर्य वाले पर्यटन के साथ–साथ धार्मिक पर्यटन के विकास की सम्भावनायें उत्तराखण्ड में विद्यमान है। पर्यटन विकास को हमारे अध्ययन के आधे से अधिक उत्तरदाता क्षेत्र के विकास की रणनीति का केन्द्र बिन्दु मानते हैं।

तालिका संख्या–10
विकास की वैकल्पिक रणनीति के सम्बन्ध में सुझाव

उत्तरदाताओं के सुझाव	कुमायूं	गढवाल	कुल	प्रतिशत
(1) पर्यटन	16	11	27	54
(2) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर व इलैक्ट्रानिक सामानों का विकास	9	3	12	24
(3) पन बिजली परियोजनायें	5	10	15	30
(4) अवस्थापना विकास	12	6	18	36
(5) बागवानी, फूलों की खेती, मछली पालन और पशुधन विकास	9	11	20	40
(6) वन संरक्षण व वन आधारित उद्योग	6	7	13	26
(7) जड़ी बूटी	10	8	18	36
(8) लघु एवं कुटीर उद्योग विकास	11	5	16	32
(9) क्षेत्रीय आवश्यकताओं व दशाओं के अनुसार योजनाए बनाना	2	1	3	6
(10) पर्यावरण संरक्षण	2	2	4	8
(11) चाय बागान	3	1	4	8

बागवानी, फूलों की खेती, मछली पालन व पशुधन विकास पर बल देने की बात 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कही। उत्तराखण्ड की जलवायु, बागवानी, फल व मौसमी सब्जियों के लिए बहुत ही उपयुक्त है इस लिए वहॉ फलों पर आधारित छोटे–छोटे उद्योग स्थापित किये जा सकते है। बागवानी के अलावा फूलों की खेती, मछली पालन व पशुधन विकास की काफी सम्भावनायें विद्यमान है। उत्तरदाताओं ने कृषि व पशुपालन विकास पर अधिक बल दिया।

अवस्थाना विकास किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अवस्थापना विकास से न केवल कृषि व उद्योगों का विकास होता है, वरन् मानव समाज के सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक विकास में भी मदद मिलती है। एक तिहाई से अधिक उत्तरदाताओं ने अवस्थापना विकास पर अधिक ध्यान देने का सुझाव दिया।

लगभग एक तिहाई उत्तरदाताओं ने पन बिजली परियोजनाओं को बढावा देने की बात कही, उत्तराखण्ड में जिसकी बड़ी सम्भावनायें विद्यमान है। बिजली उत्पादन से न केवल उत्तराखण्ड की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, वरन् उत्तराखण्ड की राज्य सरकार बिजली का वाणिज्यिक उपयोग करके आय का सृजन भी कर सकती है, पनबिजली विकास की सम्भावनायें गढ़वाल मण्डल में अधिक हैं, जहां प्रचुर जल संसाधन उपलब्ध हैं। अतः गढ़वाल मण्डल के लगभग आधे उत्तरदाता पनबिजली विकास का समर्थन करते हैं। जबकि कुमायूं मण्डल के बीस प्रतिशत से कम उत्तरदाता इसके पक्ष में हैं।

उत्तराखण्ड के जंगलो में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों का अपार भण्डार विद्यमान है, जिसका उपयोग पर्वतीय क्षेत्रों मे रहने वाले लोग अभी तक कर रहे हैं और जो अचूक दवा का कार्य भी करते हैं। इनके विकास की उत्तराखण्ड में काफी सम्भावनायें है। 36.0 प्रतिशत उत्तरदाता जड़ी बूटी से सम्बन्धित उद्योग को बढावा देने के सुझाव के पक्ष में हैं।

पर्वतीय क्षेत्रों में कम्प्यूटर साफ्टवेयर व इलेक्ट्रानिक उद्योग पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त है। हमारे 24.0 प्रतिशत उत्तरदाता इन उद्योगों को बढ़ावा देने का सुझाव देते है। उत्तराखण्ड के विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण तथा चाय बागानी का सुझाव भी कुछ उत्तरदाताओं ने दिया। कुछ अन्य उत्तरदाताओं का यह मत था कि उत्तराखण्ड की योजना वहॉ की आवश्यकताओं व दिशाओं के अनुसार बनाने का प्रयास होना चाहिये।

संक्षेप में उत्तराखण्ड के विकास की वैकल्पिक रणनीति के जो सुझाव प्राप्त हुये हैं, वे वहां की प्राकृतिक सम्पदा व परिस्थितियों के अनुरूप हैं। गढ़वाल मण्डल व कुमायूं मण्डल की भौगोलिक परिस्थितियों के अन्तर को ध्यान में रखते हुए, दोनों मण्डलों के उत्तरदाताओं की विकास की प्राथमिकताओं में ध्यान देने योग्य अन्तर सर्वेक्षण में उभर कर आये हैं। कुमायूं मण्डल के उत्तरदाताओं ने अवस्थापना विकास, लघु उद्योगों के विकास तथा कम्प्यूटर साफ्टवेयर के विकास पर अधिक बल दिया है। दूसरी ओर, गढवाल मण्डल के उत्तरदाताओं ने बागवानी, फूलों की खेती, पनबिजली परियोजनाओं तथा जड़ी-बूटी के विकास पर अधिक बल दिया। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने का समर्थन दोनों ही मण्डलों के उत्तरदाताओं ने समान रूप से किया। हमारा अध्ययन यह संकेत देता है कि एक ही प्रकार की विकास रणनीति सम्पूर्ण उत्तराखण्ड के लिये उपयुक्त नही होगी।

राज्य पुनर्गठन के सम्बन्ध में विचार

उत्तर पदेश सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिये 1973 में एक पृथक पर्वतीय विकास विभाग बनाया था। उत्तरदाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या यह विभाग लोगों की आकांक्षाओं व आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफल रहा अथवा नहीं? इस प्रश्न के उत्तर में हमारे 68.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पर्वतीय विकास विभाग को पूर्णतया असफल माना तथा 28.0 प्रतिशत ने इसको आंशिक रुप से विफल माना (तालिका संख्या-11)। मात्र 4.0 प्रतिशत लोग पर्वतीय विकास विभाग के सफल होने की बात को स्वीकारते है।

पर्वतीय विकास विभाग के असफल होने के कारणों के सम्बन्ध में 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में जो धन का आवंटन किया गया वह अपर्याप्त था और उसका उचित उपयोग भी नहीं किया गया। 28.0 प्रतिशत का मत था कि पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए बनायी जाने वाली योजनायें वहॉ की आवश्यकता के अनुसार नही थी। 24.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अक्षम कर्मचारियों का होना व कर्मचारियों की न्यूनता के कारण पर्वतीय विकास विभाग के असफल होने की बात की है। 14 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पर्वतीय सम्भाग की अवहेलना को व 8 प्रतिशत ने धन के असमान वितरण को पर्वतीय विकास विभाग की असफलता का कारण बताया है।

हमारे 70 प्रतिशत उत्तरदाता इस विचार से पूर्णतया सहमत थे कि उत्तराखण्ड का पृथक राज्य बनने से लोगों को अच्छा प्रशासन मिलेगा व विकास की सम्भावनायें बढ़ेंगी। 21.0 प्रतिशत उत्तरदाता आंशिक रुप से इससे सहमत पाये गये। गढ़वाल मण्डल के शत-प्रतिशत उत्तरदाता इस विचार से सहमत पाये गये, जबकि कुमायूॅ क्षेत्र के 3 उत्तरदाता इस बात से सहमत नहीं थे।

सामान्य रूप से अधिकांश उत्तरदाता देश के राज्यों के छोटे राज्यों के रूप में पुर्नगठन की आवश्यकता से सहमत हैं। 78.0 प्रतिशत उत्तरदाता उत्तर प्रदेश को 3-4 छोटे राज्यों में विभक्त करने के पक्ष में हैं जबकि 22 प्रतिशत इसके विरोध में हैं। भारत को छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित करने के लिए 66.0 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाये गये, जबकि एक तिहाई उत्तरदाता इसका विरोध करते हैं।

76.0 प्रतिशत उत्तरदाता विशिष्ट क्षेत्रों को अलग राज्य बनाने के पक्ष में है। जहाँ तक नये राज्यों के सृजन की कसौटियों का प्रश्न है, 68.0 प्रतिशत उत्तरदाता वित्तीय व आर्थिक आत्मनिर्भरता को, 64.0 प्रतिशत उत्तरदाता भैगोलिक समानता को और 48.0 प्रतिशत उत्तरदाता सांस्कृतिक समानता को राज्य के सृजन की प्रमुख कसौटी मानते है। 32.0 प्रतिशत उत्तरदाता आर्थिक रामानता को व 12 प्रतिशत जाति की समानता को नये राज्य के सृजन की कसौटी मानते है।

तालिका संख्या–11
राज्य पुर्नगठन के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के विचार

उत्तरदाताओं के विचार	कुमायूं	गढ़वाल	कुल	प्रतिशत
1. क्या उत्तराखण्ड विकास विभाग का सृजन असफल रहा ?				
(1) पूर्णतया सहमत	19	15	34	68
(2) आंशिक रूप से सहमत	8	6	14	28
(3) असहमत	2	-	2	4
यदि सहमत है तो कारण				
(1) पर्वतीय क्षेत्र की उपेक्षा	4	3	7	14
(2) धन का असमान वितरण	2	2	4	8
(3) धनराशि की कमी व उसका अनुचित उपयोग	12	8	20	40
(4) स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजना न बनना	8	6	14	28
(5) सक्षम अधिकारी और कर्मचारियों की न्यूनता	8	4	12	24
2. क्या अलग राज्य अच्छे प्रशासन व विकास में सहायक होगा?				
(1) पूर्णतया सहमत	18	17	35	70
(2) आंशिक रूप से सहमत	8	4	12	24
(3) असहमत	3	-	3	6
3. क्या आप उत्तर प्रदेश को 3– 4 भागों में बांटने के पक्ष में है?				
(1) हॉ	21	18	39	78
(2) नही	8	3	11	22
4. क्या आप भारत को छोटे राज्यों मे बाटने के पक्ष मे है?				
(1) हॉ	20	13	33	66
(2)नहीं	9	8	17	34
5. क्या आप विशिष्ट क्षेत्रों को अलग राज्य बनाने के पक्ष में हैं ?				
(1) हॉ	21	17	38	76
(2) नही	8	4	12	24
6. नये राज्य सृजन का उचित आधार क्या होना चाहिए?				
(1) सांस्कृतिक समानता	13	11	24	48
(2) भौगोलिक समानता	18	14	32	64
(3) आर्थिक समानता	10	6	16	32
(4) वित्तीय व आर्थिक आत्मनिर्भरता	19	15	34	68
(5) जाति की समानता	3	3	6	12
7. उत्तराखण्ड राज्य वित्तीय व आर्थिक रूप से सक्षम राज्य होगा ?				
(1) हॉ	22	17	39	78
(2) नही	7	4	11	22
8. राज्य को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के उपाय				
(1) केन्द्र अधिक धन दे	19	14	33	66
(2) क्षेत्रीय संसाधनो के उपयोग पर अधिक रायल्टी	17	16	33	66
(3) जन सहभागिता	12	8	20	40
(4) वाणिज्यक उपयोग के लिए पन बिजली का उपयोग	8	4	12	24

हमने उत्तरदाताओं से यह जानने का भी प्रयास किया कि क्या उत्तराखण्ड राज्य वित्तीय व आर्थिक रुप से अपने आप में सक्षम राज्य होगा ? 80.0 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते है कि उत्तराखण्ड राज्य वित्तीय व आर्थिक रुप से सक्षम होगा, लेकिन 20.0 प्रतिशत इस पर संदेह करते हैं। उत्तराखण्ड को वित्तीय व आर्थिक रुप से सक्षम बनाने के सुझावों के सम्बन्ध में 68.0 प्रतिशत उत्तरदाता इस विचार के हैं कि क्षेत्रीय संसाधनों के उपयोग पर राज्य को अधिक रायल्टी दी जाय तथा अधिक केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाये। 40.0 प्रतिशत लोग जन सहभागिता की उम्मीद करते है, 24.0 प्रतिशत उत्तरदाता पन बिजली का उत्पादन करके उसका वाणिज्यिक उपयोग करने का सुझाव देते है। इन उत्तरों से यह स्पष्ट होता है कि केन्द्र से अधिक धनराशि दे कर व रायल्टी आदि के सम्बन्ध मे केन्द्र की नीतियों में सुधार करके ही उत्तराखण्ड को एक आर्थिक रूप से सक्षम राज्य बनाया जा सकता है। आतंरिक वित्तीय संसाधनों को जुटाने की बात किसी ने नहीं कही।

उत्तराखण्ड आन्दोलन के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के विचार

हमारे अध्ययन का एक प्रमुख उद्देश्य यह जानना था कि उत्तराखण्ड निवासी उत्तराखण्ड आन्दोलन से जुड़े विभिन्न मुद्दों के बारे में क्या विचार रखते है ? यथा उत्तराखण्ड आन्दोलन किस तरह का आन्दोलन था ? इसकी शुरुआत कब से हुई ? आन्दोलन को किन तत्वों व घटनाओं से शक्ति मिली ? इन प्रश्नों से जुड़े उत्तरों का विवरण तालिका संख्या–12 में दर्शाया गया है। अधिकांश उत्तरदाता (86.0 प्रतिशत) उत्तराखण्ड आन्दोलन को एक जन आन्दोलन के रूप में देखते हैं, जबकि लगभग 6.0 प्रतिशत उत्तरदाता इस आंदोलन को प्रभावशाली वर्ग व 6.0 प्रतिशत मध्यवर्गीय लोगों का आन्दोलन मानते हैं (तालिका संख्या–12)। मात्र एक उत्तरदाता उत्तराखण्ड आन्दोलन को निम्न वर्ग का आन्दोलन मानता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उत्तराखण्ड आन्दोलन को क्षेत्र के लगभग सभी व्यक्तियों व वर्गों का समर्थन प्राप्त था।

तालिका संख्या–12
उत्तराखण्ड आन्दोलन के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के विचार

उत्तरदाताओं के विचार	कुमायू	गढ़वाल	कुल	प्रतिशत
1. उत्तराखण्ड आन्दोलन किस तरह का आन्दोलन है ?				
(1) जन आन्दोलन	25	18	43	86
(2) प्रभावशाली वर्गों का एक सीमित आन्दोलन	2	1	3	6
(3) निम्न वर्ग के लोगों का आन्दोलन	1	-	1	2
(4) मध्यम वर्ग के लोगों का आन्दोलन	1	2	3	6
2. उत्तराखण्ड आन्दोलन कब से प्रबल हुआ?				
(1) आजादी के समय से	1	2	3	6
(2) 1952 से	-	1	1	2
(3) 1971 , 1981 के मध्य	5	-	5	10
(4) 1992 , 1996 के मध्य	23	18	41	82
(5) 1994 के आरक्षण आन्दोलन से	16	12	28	56
3. उत्तराखण्ड आन्दोलन को शक्ति देने वाले तत्व				
(1) आर्थिक पिछड़ापन	1	1	2	4
(2) केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा उपेक्षा	2	-	2	4
(3) स्थानीय बुद्धिजीवी व पत्रकारों की भूमिका	3	1	4	8
(4) कर्मचारी संघ की भूमिका	4	-	4	8
(5) महिला, बेरोजगार और छात्र संघ की भूमिका	5	3	8	16
(6) उत्तराखण्ड क्रान्ति दल की भूमिका	1	-	1	2
(7) आरक्षण विरोधी लहर	5	5	10	20
(8) मसूरी खटिमा और मुजफ्फरनगर काण्ड	9	12	21	42
(9) दोषपूर्ण वन नीति	1	-	1	2

हमने उत्तरदाताओं से यह जानने का भी प्रयास किया कि उत्तराखण्ड आन्दोलन की शुरुआत उनके अनुसार कब से हुई। हमारे अध्ययन के इने गिने (8.0 प्रतिशत) उत्तरदाता यह मानते है कि उत्तराखण्ड आन्दोलन आजादी के समय या उसके तुरन्त बाद प्रारम्भ हुआ। प्रारम्भ के वर्षो में असंतोष के स्वर मंद व अस्फुटित ही रहे और उन्हें सत्ताधारी अथवा विरोधी राजनैतिक दलों का समर्थन नहीं मिला। सत्तर के दशक से असंतोष के स्वर अधिक तीव्रता से मुखरित होना प्रारम्भ हुये। हमारे अध्ययन के 10.0 प्रतिशत उत्तरदाता उत्तराखण्ड आन्दोलन की शुरुआत सन् 1971–81 के दशक से मानते है। यह उल्लेखनीय है कि ये सभी उत्तरदाता कुमायूँ मण्डल के ही हैं। उस समय कुमायें मण्डल ही उत्तराखण्ड आन्दोलन चलाने में अग्रिम पंक्ति में खड़ा था और उत्तराखण्ड क्रान्ति दल व उत्तराखण्ड जन संघर्ष वाहिनी का नेतृत्व कुमाऊंनी नेताओं के हाथ में था।

इन स्वरों को सम्पूर्ण उत्तराखण्ड की एक आवाज लेकर उभरने में लगभग दो दशकों का समय और लगा। जिस बात ने एक अंगारे को वनाग्नि का रूप दिया वह थी मुलायम सिंह सरकार द्वारा पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण की घोषणा, जिसने क्षेत्र के बहुसंख्यक वर्ग के आर्थिक हितों और रोजगार की सम्भावनाओं पर सीधा व गहरा कुठाराघात किया। फलतः सम्पूर्ण उत्तराखण्ड से विरोध का एक समवेत स्वर उभरा। हमारे अध्ययन के लगभग 82.0 प्रतिशत उत्तरदाता उत्तराखण्ड आन्दोलन की असली शुरुआत 1992 से 1996 के बीच में मानते है। 56.0 प्रतिशत उत्तरदाता आन्दोलन का मुख्य कारण सरकार की 1994 की आरक्षण नीति मानते हैं।

उत्तराखण्ड आन्दोलन को शक्ति प्रदान करने वाले कारकों में उत्तरदाताओं ने आरक्षण विरोधी लहर तथा मसूरी, खटीमा व मुजफ्फरनगर की घटनाओं को सबसे अधिक महत्व दिया (तालिका सं0 12)। आन्दोलन की तीव्रता प्रदान करने में बेराजगार नवयुवकों, कर्मचारी संघों व बुद्धिजीवियों की बड़ी भूमिका रही। स्पष्ट है कि ये सभी वर्ग आरक्षण नीति से आशंकित थे, जिसने उनके भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। उत्तराखण्ड आन्दोलन के पीछे भावनात्मक प्रवृतियां अधिक प्रबल थीं, जिनको राजनैतिक व प्रशासनात्मक स्तर की गलतियों ने जन्म दिया। यहां उल्लेखनीय है कि आन्दोलन को बल प्रदान करने वाले कारकों में केवल 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ही आर्थिक पिछड़ेपन, राज्य व केन्द्रीय सरकार द्वारा उपेक्षा अथवा गलत वन नीति का उल्लेख किया।

उत्तराखण्ड आन्दोलन में विभिन्न सामाजिक वर्गों की भूमिका

हमने सर्वेक्षण के माध्यम से उत्तराखण्ड आन्दोलन के सामाजिक आधार को देखने का प्रयास किया। उत्तरदाताओ के अनुसार सबसे अधिक दृढ़ समर्थन आन्दोलन को विद्यार्थियों, महिलाओं तथा भूतपूर्व सैनिकों से प्राप्त हुआ (तालिका सं013)। अधिकांश सरकारी कर्मचारी भी आन्दोलन के साथ थे। कृषक वर्ग भी आन्दोलन का समर्थन कर रहा था। उत्तरादाताओं के आंकलन में सबसे कम समर्थन देने वाले वर्गों में व्यापारिक वर्ग था, जो आरक्षण नीति से अधिक प्रभावित नहीं था।

जातिवार समर्थन के सम्बन्ध में उत्तरों का विश्लेषण दर्शाता है कि उच्च जाति वर्ग के लगभग सभी लोग उत्तराखण्ड, आन्दोलन के दृढ़ समर्थक थे। यही वर्ग आरक्षण नीति से सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। पिछड़ी व अनुसूचित जातियों का समर्थन अधिकांश लोगों ने औसत या निम्न स्तर का आंका है। ये जातियाँ आरक्षण से अधिक लाभान्वित हो रही थी।

तालिका संख्या–13

विभिन्न समूहों द्वारा उत्तराखण्ड आन्दोलन को समर्थन

वर्ग	कुमायूं	गढ़वाल	कुल	प्रतिशत
1. व्यावसायिक वर्ग				
(1) दृढ़ता से	9	8	17	34
(2) औसतन	8	8	16	32
(3) थोड़ा	12	5	17	34
2. सरकारी कर्मचारी				
(1) दृढ़ता से	18	13	31	62
(2) औसतन	7	7	14	28
(3) थोड़ा	4	1	5	10
3. विद्यार्थी				
(1) दृढ़ता से	26	20	46	92
(2) औसतन	3	1	4	8
(3) थोड़ा	-	-	-	-
4. भूतपूर्व सैनिक				
(1) दृढ़ता से	23	20	43	86
(2) औसतन	4	1	5	10
(3) थोड़ा	2	-	2	4
5. महिलायें				
(1) दृढ़ता से	21	18	39	78
(2) औसतन	6	3	9	18
(3) थोड़ा	2	-	2	4
6. कृषक				
(1) दृढ़ता से	12	13	25	50
(2) औसतन	11	7	18	36
(3) थोड़ा	6	1	7	14
7. अन्य				
(1) दृढ़ता से	8	7	15	30
(2) औसतन	13	8	21	42
(3) थोड़ा	8	6	14	28
8. उच्च जाति				
(1) दृढ़ता से	24	19	43	86
(2) औसतन	2	2	4	8
(3) थोड़ा	3	-	3	6
9. पिछड़ी जाति				
(1) दृढ़ता से	10	7	17	34
(2) औसतन	10	10	20	40
(3) थोड़ा	9	4	13	26
10. अनुसूचित जाति				
(1) दृढ़ता से	11	4	15	30
(2) औसतन	8	12	20	40
(3) थोड़ा	10	5	15	30

11. बड़े शहरों से				
(1) दृढता से	21	15	36	72
(2) औसतन	5	5	10	20
(3) थोड़ा	3	1	4	8
12. छोटे शहरों से				
(1) दृढता से	17	15	32	64
(2) औसतन	8	5	13	26
(3) थोड़ा	4	1	5	10
13. ग्रामीण क्षेत्र				
(1) दृढता से	16	14	30	60
(2) औसतन	8	6	14	28
(3) थोड़ा	5	1	6	12

आन्दोलन का क्षेत्रीय विस्तार भी उत्तराखण्ड के सभी अंचलों, नगरों व ग्रामों में फैला था। हमारे 18.0 प्रतिशत उत्तरदाता बड़े शहरों से आन्दोलन को दृढ़तापूर्व समर्थन मिलने की बात स्वीकारते है, जबकि 8.0 प्रतिशत उत्तरादाता छोटे शहरों से भी और 6.0 प्रतिशत उत्तरादाता ग्रामीण क्षेत्र से भी आन्दोलन को सबल समर्थन होने की बात को स्वीकारते है। 68.0 प्रतिशत उत्तरदाता सभी क्षेत्रों से आन्दोलन को समर्थन मिलने की बात करते हैं। फिर भी बड़े शहरों में शिक्षण संस्थाओं व बुद्धिजीवियों का बाहुल्य होने के कारण यहां से मिलने वाला समर्थन अपेक्षाकृत अधिक रहा। संक्षेप में, हमारा सर्वेक्षण उत्तराखण्ड आन्दोलन के व्यापक जन समर्थन की पुष्टि करता है, जिसमें अधिकांश सामाजिक वर्गों व क्षेत्रों की भागीदारी रही है।

हमने उत्तरदाताओं से यह भी जानने का प्रयास किया कि उत्तराखण्ड आन्दोलन में मुख्य नेतृत्व समाज के किन वर्गों से उभरा है ? प्राप्त उत्तरों के आधार पर पाया गया कि मुख्य रूप से आन्दोलन का नेतृत्व छात्रों, बेरोजगार नवयुवकों व भूतपूर्व सैनिकों द्वारा किया गया। यही वर्ग आरक्षण नीति का अधिक विरोध कर रहे थे। लगभग सभी उत्तरादाता यह स्वीकारते है कि महिलायें विशेषरूप से आन्दोलन मे अग्रणी रही (तालिका संख्या–13)। महिलाओं पर हुयी ज्यादातियों ने महिलाओं को आक्रोशित किया और वह आन्दोलन में कमर कस के शामिल हुयीं।

हमारे अध्ययन के उत्तरदाताओं के अनुसार अन्य वर्गों यथा व्यापारिक वर्ग, कृषक वर्ग, व्यावसायिक वर्ग आदि से नेतृत्व औसत अथवा सीमित रूप से उभरा है।

हमने अध्ययन में यह भी जानने का प्रयास किया कि उत्तराखण्ड आन्दोलन को चलाने वाले विभिन्न वर्ग के लोग किस आयु वर्ग के थे ? इस प्रश्न के उत्तर में 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आन्दोलनकारियों के नेतृत्व की आयु 35 से 55 वर्ष के बीच बतायी, जबकि 30 प्रतिशत ने मुख्यतः नवयुवकों की आन्दोलन में अधिक भागीदारी बतायी (तालिका संख्या–14)। 55 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों के द्वारा उत्तराखण्ड आन्दोलन में नेतृत्व प्रदान करने के सम्बन्ध में 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सहमति व्यक्त की है। यह विश्लेषण दर्शाता है कि उत्तराखण्ड आन्दोलन में सभी आयु वर्ग के लोग सक्रिय रहे हैं।

तालिका संख्या–14
आन्दोलन को नेतृत्व प्रदान करने वाले वर्गो का विवरण

वर्ग	कुमायूं	गढ़वाल	कुल	प्रतिशत
1. व्यावसायिक वर्ग				
(1) दृढ़ता से	8	5	13	26
(2) औसतन	11	8	19	38
(3) थोड़ा	10	8	18	36
2. सरकारी कर्मचारी				
(1) दृढ़ता से	18	11	29	58
(2) औसतन	9	9	18	36
(3) थोड़ा	2	1	3	6
3. बेरोजगार नवयुवक				
(1) दृढ़ता से	20	17	37	74
(2) औसतन	9	4	13	26
(3) थोड़ा	-	-	-	-
4. विद्यार्थी				
(1) दृढ़ता से	21	15	36	72
(2) औसतन	4	6	10	20
(3) थोड़ा	4	-	4	8
5. भूतपूर्व सैनिक				
(1) दृढ़ता से	16	16	32	64
(2) औसतन	10	5	15	30
(3) थोड़ा	3	-	3	6
6. महिलायें				
(1) दृढ़ता से	22	17	39	78
(2) औसतन	6	3	9	18
(3) थोड़ा	1	1	2	4
7. कृषक				
(1) दृढ़ता से	10	8	18	36
(2) औसतन	11	8	19	38
(3) थोड़ा	8	5	13	26
8. व्यापारी				
(1) दृढ़ता से	7	5	12	24
(2) औसतन	14	9	23	46
(3) थोड़ा	8	7	15	30
9. अन्य				
(1) दृढ़ता से	10	5	15	30
(2) औसतन	16	2	18	36
(3) थोड़ा	3	14	17	34
10. नेतृत्व प्रदान करने वालों का आयु वर्ग				
(1) मुख्यतया युवावर्ग	8	7	15	30
(2) मध्य आयु वर्ग	11	8	19	38
(3) वृद्ध लोग	10	6	16	32
11. जहां से नेतृत्व उभरा				
(1) मुख्यत बड़े शहर	4	5	9	18
(2) मुख्यत छोटे शहर	2	2	4	8
(3) मुख्यत ग्रामीण क्षेत्र	2	1	3	6
(4) सभी क्षेत्र	21	13	34	68
12. अप्रवासियो का सहयोग				
(1) कड़ा समर्थन	15	13	28	56
(2) औसत समर्थन	14	8	22	44
(3) कम समर्थन	-	-	-	-

उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास भी किया गया कि उत्तराखण्ड आन्दोलन को नेतृत्व किन क्षेत्रों से मिला है। इस प्रश्न के उत्तर में 68 प्रतिशत उत्तरदाता उत्तराखण्ड के सभी क्षेत्रों से आन्दोलन का नेतृत्व उभरने की बात को स्वीकारते है। जबकि 18.0 प्रतिशत उत्तरदाता आन्दोलन के नेतृत्व को बड़े शहरों से उभरने की बात करते हैं। उत्तराखण्ड से बाहर गये हुये अप्रवासियों ने भी आन्दोलन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। आधे से अधिक उत्तरदाताओं ने प्रवासियों के योगदान को अति सराहनीय तथा शेष ने सराहनीय बताया।

उत्तराखण्ड आन्दोलन में राजनैतिक दलों की भूमिका

हमने उत्तरदाताओं से आन्दोलन के कुछ अन्य पहलुओं जैसे दलबन्दी व गुटबन्दी का पाया जाना, विभिन्न राजनैतिक दलों व गैर राजनैतिक संगठनों की आन्दोलन में भूमिका, और आन्दोलन में सक्रिय रुप से भाग लेने वाले प्रमुख नेताओं के नाम भी आमंत्रित किये। इन पहलुओं के सम्बन्धित उत्तरों को तालिका संख्या–15 में दर्शाया गया है।

हमारे अध्ययन के 56.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उत्तराखण्ड आन्दोलन के नेतृत्व को दलबन्दी व गुटबन्दी का शिकार होने की बात स्वीकारी है। प्रत्येक राजनैतिक दल अपने दल की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आन्दोलन का श्रेय लेना चाहते थे और राजनैतिक शक्ति को हासिल करने के लिए सक्रीय थे। इसके साथ–साथ राजनैतिक दलों में आपसी सामंजस्य का आभाव भी रहा और सभी दलों को मिलकर चलाने के लिए नेतृत्व नहीं उभर पाया। कुछ का यह भी मानना था कि भारतीय जनता पार्टी विलम्ब से उत्तराखण्ड आन्दोलन को समर्थन देने के लिये सामने आयी। लगभग एक तिहाई उत्तरदाताओं ने मत व्यक्त किया कि विभिन्न राजनैतिक दल राजनैतिक लाभ के लिये ही आन्दोलन का उपयोग कर रहे थे। लेकिन दो–तिहाई उत्तरदाताओं ने इसका खण्डन किया।

तालिका संख्या–15
उत्तराखण्ड आन्दोलन में राजनीतिक दलों की भूमिका के बारे में विचार

पहलू	कुमायूं	गढ़वाल	कुल	प्रतिशत
1. क्या आप सोचते है उत्तराखण्ड आन्दोलन दलबन्दी का शिकार है ?				
(i) हां	16	12	28	56
(ii) नही	13	9	22	44
2. क्या आप मानते है कि				
(i) राजनैतिक दल केवल अपनी साख बढ़ाने के लिए आन्दोलन में थे	5	3	8	16
(ii) राजनैतिक दल अपनी शक्ति बढ़ाने में सक्रीय थे	4	2	6	12
(iii) दलों में सहयोग का अभाव	4	2	6	12
(iv) नेतृत्व का अभाव	2	3	5	10
(v) भाजपा द्वारा विलम्ब से आन्दोलन को समर्थन	1	2	3	6
3. क्या आप सोचते है कि राजनैतिक दल राजनीतिक फायदे के लिए आन्दोलनों का उपयोग कर रहे थे				
(i) हॉ	9	9	18	36
(ii) नही	20	12	32	34
4. विभिन्न दलों की आन्दोलन में भूमिका				
बी० जे० पी०				
(1) बहुत ईमानदार	10	1	11	22
(2) ईमानदार	6	9	15	30
(3) कम ईमानदार	8	10	18	36
(4) नकारात्मक	5	1	6	12

कांग्रेस				
(1) बहुत ईमानदार	2	1	3	6
(2) ईमानदार	8	5	13	26
(3) कम ईमानदार	13	13	26	52
(4) नकारात्मक	6	2	8	16
समाजवादी पार्टी				
(1) बहुत ईमानदार	-	1	1	2
(2) ईमानदार	3	2	5	10
(3) कम ईमानदार	6	7	13	26
(4) नकारात्मक	20	11	31	62
बहुजन समाज पार्टी				
(1) बहुत ईमानदार	-	2	2	4
(2) ईमानदार	4	3	7	14
(3) कम ईमानदार	8	8	16	32
(4) नकारात्मक	17	8	25	50
सी0 पी0 आई0				
(1) बहुत ईमानदार	3	10	13	26
(2) ईमानदार	6	4	10	20
(3) कम ईमानदार	6	5	11	22
(4) नकारात्मक	14	2	16	32
उत्तराखण्ड क्रान्तिदल				
(1) बहुत ईमानदार	16	16	32	64
(2) ईमानदार	5	3	8	16
(3) कम ईमानदार	8	2	10	20
(4) नकारात्मक	-	-	-	-
सी0 पी0 आई0 एम0				
(1) बहुत ईमानदार	-	-	-	-
(2) ईमानदार	3	1	4	8
(3) कम ईमानदार	4	5	9	18
(4) नकारात्मक	22	15	37	74
अन्य				
(1) बहुत ईमानदार	4	2	6	12
(2) ईमानदार	1	1	2	4
(3) कम ईमानदार	2	2	4	8
(4) नकारात्मक	22	16	38	76

जहाँ तक विभिन्न राष्ट्रीय राजनैतिक दलों का प्रश्न है उनमें कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी प्रारम्भ से ही उत्तराखण्ड पृथक राज्य के पक्ष मे नही रही । सन् 1994 के आरक्षण विरोधी आन्दोलन के बाद ही कांग्रेस पार्टी उत्तराखण्ड मे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सक्रिय हुई। हमारे अध्ययन के मात्र 32 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कांग्रेस द्वारा ईमानदारी से आन्दोलन में अपनी भूमिका निभाने की पुष्टि की। 52.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कांग्रेस द्वारा कम ईमानदारी से आन्दोलन में अपनी भूमिका निभाने की बात की तथा 16.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल द्वारा उत्तराखण्ड आन्दोलन में नकारात्मक भूमिका निभाने की बात की। भारतीय जनता पार्टी भी प्रारम्भ से ही आन्दोलन में सक्रिय नही रही लेकिन जब स्थानीय राजनैतिक दलों ने आन्दोलन को पृथक राज्य मिलने की स्थिति मे ला खड़ा कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी पृथक राज्य आन्दोलन में सक्रिय होने लगी। हमारे अध्ययन के लगभग 22.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत ईमानदारी से और 30.0 प्रतिशत ने ईमानदारी से आन्दोलन में अपनी भूमिका निभाने की बात की है, लेकिन 36.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कम ईमानदारी से आन्दोलन मे भूमिका निभाने की बात की है। 12.0 प्रतिशत उत्तरदाता भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखण्ड आन्दोलन में नकारात्मक भूमिका होने की बात को भी स्वीकारते है।

समाजवादी पार्टी ने जहाँ एक ओर सर्वप्रथम उत्तराखण्ड को पृथक राज्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा में पृथक राज्य बिल पास कराया था, वही दूसरी तरफ उत्तराखण्ड क्षेत्र में पिछड़े वर्गो को आरक्षण देने की व्यवस्था की। जिसके कारण सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में जन,आन्दोलन हुए। हमारे 62.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उत्तराखण्ड आन्दोलन मे समाजवादी पार्टी की नकारात्मक भूमिका की बात की है, जबकि मात्र एक उत्तरदाता ने समाजवादी पार्टी के बहुत ईमानदारी से 10.0 प्रतिशत ने ईमानदारी से तथा 28.0 प्रतिशत ने बहुत कम ईमानदारी से उत्तराखण्ड आन्दोलन में भूमिका निभाने की बात की है।

बहुजन समाजपार्टी भी उत्तर प्रदेश के मैदानी जिला उधमसिंह नगर को उत्तराखण्ड में न मिलाने की शर्त पर उत्तराखण्ड आन्दोलन का विरोध करती रही है। हमारे 50 प्रतिशत उत्तरदाता बहुजन समाज पार्टी का उत्तराखण्ड आन्दोलन में नकारात्मक रवैया होने की बात करते है जबकि 32.0 प्रतिशत उसकी भूमिका को कम ईमानदार मानते हैं। केवल 18 प्रतिशत उसकी ईमानदारी से आन्दोलन में भूमिका निभाने की बात स्वीकारते हैं।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी छोटे राज्यों के पक्ष में रही है। उत्तराखण्ड को पृथक राज्य बनाने के सम्बन्ध में सर्वप्रथम कामरेड पी0 सी0 जोशी ने मुहिम छेड़ी थी। इसी का प्रभाव रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तराखण्ड को पृथक राज्य बनाने में अपना सहयोग देती रही है। हमारे अध्ययन के 48.0 प्रतिशत उत्तरदाता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा उत्तराखण्ड आन्दोलन में ईमानदारी से भाग लेने की बात को स्वीकारते है जबकि, 32.0 प्रतिशत उत्तरदाता उत्तराखण्ड आन्दोलन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नकारात्मक रूख होने की बात करते हैं और 22 प्रतिशत उसकी भूमिका कम ईमानदार मानते हैं।

जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि एक स्थानीय राजनैतिक दल के रूप में उत्तराखण्ड क्रान्ति दल का जन्म पृथक राज्य गठन की राजनीति से हुआ था। पृथक राज्य आन्दोलन की शुरूआत तथा समय–समय पर धरने, प्रदर्शन व हड़ताल के माध्यम से उत्तराखण्ड के आम लोगों तक पैठ इसी दल ने बनायी थी। 64.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उत्तराखण्ड आन्दोलन में उत्तराखण्ड क्रान्ति दल द्वारा बहुत ईमानदारी से तथा 16.0 प्रतिशत ने ईमानदारी से भाग लेने की बात को स्वीकारा है। जबकि 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कम ईमानदारी से यू0 के0 डी0 द्वारा आन्दोलन में भाग लेने की बात की है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) हमेशा छोटे–छोटे राज्यों का विरोध करती आयी है। हमारे अध्ययन के 74.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा सी0 पी0 आई0 (एम0) की उत्तराखण्ड आन्दोलन में नकारात्मक भूमिका होना बताया गया तथा 18.0 प्रतिशत ने सी0 पी0 आई0 (एम0) की कम ईमानदारी से आन्दोलन का समर्थन की करने बात की। अन्य छोटे–छोटे राजनैतिक दलों, विशेषकर विभिन्न दलों से टूटकर बने राजनैतिक गुटों की भूमिका को अधिकांश रूप से नकारात्मक आंका गया।

कुल मिलाकर हमारे विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तराखण्ड आन्दोलन में उत्तराखण्ड क्रान्ति दल ने अपनी एक ईमानदार व महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है, जबकि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, व सी0 पी0 आई0 की भूमिका औसत ईमानदारी की आंकी गयी। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सी0पी0आई0(एम0) व अन्य छोटे–छोटे राजनैतिक दलों की उत्तराखण्ड आन्दोलन में भूमिका को नकारात्मक माना गया।

हमने उत्तरदाताओं से उत्तराखण्ड आन्दोलन से सक्रिय रूप से भाग लेने वाले पांच प्रभावशाली लोगो के नाम भी आमंत्रित किये थे। हमारे उत्तरदाताओं के अनुसार वरीयता क्रम में प्रथम दो स्थानों पर स्व0 श्री इन्द्रमणि बडौनी व काशी सिंह ऐरी के नाम उभर कर आये। श्री बडौनी को उत्तराखण्ड का गॉधी भी कहा जाता है। वे उत्तर प्रदेश विधान सभा में निर्दलीय विधायक चुनकर आये और उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के अध्यक्ष भी रहे। काशी सिंह ऐरी भी दो बार उत्तराखण्ड क्रान्तिदल से विधायक चुनकर उत्तर प्रदेश विधान सभा में आये और वर्षों तक उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के अध्यक्ष रहे। श्री ऐरी व स्व0 बडौनी पूरे उत्तराखण्ड मे प्रभावशाली नेता रहे है।

उत्तराखण्ड राज्य में भविष्य में आने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में विचार

उत्तराखण्ड राज्य के गठन के पश्चात जिन राजनैतिक व आर्थिक चुनौतियों का सामना करना होगा इस पर भी उत्तरदाताओं से प्रश्न पूछे गये। उनके उत्तरों को तालिका संख्या 16 में दर्शाया गया है। पहला विस्फोटक विषय नवगठित राज्य की राजधानी के चयन का ही है। उत्तराखण्ड क्रान्ति दल ने गैरसैंण नामक स्थान में उत्तराखण्ड की राजधानी का उद्घाटन आन्दोलन के दौरान कर दिया था। उस समय कांग्रेस पार्टी व अन्य सरकारी व गैर सरकारी संगठनों ने इसका समर्थन भी किया था। भारतीय जनता पार्टी के अधिसंख्य लोग गैरसैंण को राजधानी बनाने का समर्थन कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनतापार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व द्वारा अचानक देहरादून को उत्तराखण्ड की राजधानी बनाने से पूरे उत्तराखण्ड में पुनः असंतोष की लहर फैल गयी। हमारे अध्ययन के लगभग 40.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने भी राजधानी के चुनाव को बहुत बड़ी समस्या माना है व लगभग 44.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कुछ सीमा तक कठिनाई आने की बात को स्वीकारा है। कुल मिलाकर 84.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पृथक राज्य के गठन के बाद राजधानी के लिए स्थान के चुनाव की समस्या को स्वीकारा है इस समस्या का दीर्घकाल में एक सतोषप्रद हल निकालना ही होगा।

तालिका संख्या–16
उत्तराखण्ड राज्य में भविष्य में आने वाली समस्याओं पर उत्तरदाताओं के विचार

समस्यायें	कुमायूं	गढ़वाल	कुल	प्रतिशत
1. राज्य की राजधानी का चुनाव				
(1) बड़ी सीमा तक	14	6	20	40
(2) कुछ सीमा तक	9	13	22	44
(3) नगण्य	6	2	8	16
2. राजनैतिक दलों में सत्ता संघर्ष				
(1) बड़ी सीमा तक	16	14	30	60
(2) कुछ सीमा तक	9	5	14	28
(3) नगण्य	4	2	6	12
3. व्यक्तिगत महत्वकांक्षा				
(1) बड़ी सीमा तक	19	16	35	70
(2) कुछ सीमा तक	8	4	12	24
(3) नगण्य	2	1	3	6
4. कुमायूं व गढ़वाल क्षेत्रों के हितों में मतभेद				
(1) बड़ी सीमा तक	2	4	6	12
(2) कुछ सीमा तक	13	12	25	50
(3) नगण्य	14	5	19	38
5. जातिगत/सामुदायिक मतभेद				
(1) बड़ी सीमा तक	4	6	10	20
(2) कुछ सीमा तक	7	3	10	20
(3) नगण्य	18	12	30	60
6. वित्तीय संसाधनों का अभाव				
(1) बड़ी सीमा तक	13	11	24	48
(2) कुछ सीमा तक	13	7	20	40
(3) नगण्य	3	3	6	12
7. प्रशासनिक ढांचे की कमजोरी				
(1) बड़ी सीमा तक	9	9	18	36
(2) कुछ सीमा तक	17	10	27	54
(3) नगण्य	3	2	5	10

उत्तराखण्ड में मात्र कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी व भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय दल व उत्तराखण्ड क्रान्ति दल जैसे क्षेत्रीय राजनैतिक दल अस्तित्व में थे वही अब उत्तराखण्ड जनसंघर्ष वाहिनी व उत्तराखण्ड संयुक्त संघर्ष मोर्चा भी राजनैतिक दल का रूप लेने की स्थिति में आ गये हैं। हमारे अध्ययन के 60.0 प्रतिशत उत्तरदाता विभिन्न राजनैतिक दलों में एक बड़ी सीमा तक तथा 26.0 प्रतिशत उत्तरदाता कुछ सीमा तक सत्ता संघर्ष होने की सम्भावना जताते है। जबकि शेष 12.0 प्रतिशत उत्तरदाता विभिन्न राजनैतिक दलों में सत्ता संघर्ष की समस्या को अधिक महत्व नहीं देते हैं।

जहाँ विभिन्न राजनैतिक दलों में सत्ता हेतु तीव्र संघर्ष होने की सम्भावना है, वहीं विभिन्न दलों, वर्गो व प्रवासी आन्दोलनकारियो की अपनी महत्वकांक्षायें है। इन महत्वाकांक्षी व्यक्तियों का भी सत्ता हेतु टकराव अवश्य सम्भावित है। हमारे अध्ययन के लगभग 70.0 प्रतिशत उत्तरदाता बहुत अधिक सीमा तक तथा लगभग 22.0 प्रतिशत उत्तरदाता कुछ सीमा तक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षी लोगों में टकराव की सम्भावना व्यक्त करते है।

ऐतिहासिक दृष्टि से कुमाऊँनी व गढ़वाली लोगों में मतभेद व अन्तर रहे हैं, जिसके कारण पृथक राज्य बनने पर क्षेत्रीय भावना के भड़कने के कयास लगाये जाते है। लेकिन हमारे अध्ययन में 38.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पृथक राज्य में कुमाऊँ व गढ़वाल में होने वाले कलह को नगण्य ठहराया है। अन्य 50.0 प्रतिशत उत्तरदाता भी कुछ सीमा तक ही आपसी कलह की सम्भावना व्यक्त करते हैं। गढ़वाल मण्डल के उत्तरदाता कुछ अधिक सीमा तक इस विषय में आशंकित हैं, क्योंकि यह क्षेत्र पूर्व में कम विकसित रहा है।

उत्तराखण्ड क्षेत्र में कुछ राजनैतिक स्वार्थी लोगों के अलावा उत्तराखण्डी समाज के लोगो को किसी वर्ग ने भी जाति व समुदाय के रुप में बॉटनें का जहर नहीं घोला है। कुछ जातिवादी राजनैतिक दलों द्वारा जाति को राजनीति का आधार बनाये जाने के कारण जातिवाद व समुदायवाद की सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता हैं। हमारे अध्ययन के 20 प्रतिशत उत्तरदाता बहुत हद तक और 20.0 प्रतिशत अन्य उत्तरदाता कुछ सीमा तक इस समस्या की बात को स्वीकारते हैं। लेकिन अधिकांश (60.0) प्रतिशत उत्तरदाता जाति व समुदाय के कलह की बात को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, जो उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों की प्रमुख समस्या रही है।

उत्तराखण्ड राज्य के सामने विकास व प्रशासन के लिये आर्थिक संसाधनों का जुटाना एक बड़ी चुनौती है। हमारे अध्ययन के 48.0 प्रतिशत उत्तरदाता पूर्णतया व लगभग 40.0 प्रतिशत उत्तरदाता कुछ सीमा तक आर्थिक संसाधनों की कमी की समस्या स्वीकार करते हैं।

एक नये राज्य में प्रशासनिक अवस्थापना और एक नवीन विकासशील व जनता के प्रति संवेदनशील प्रशासनिक व्यवस्था व अधिकारियों की नितान्त आवश्यकता होगी, जिसके अभाव में बढ़ी हुयी अपेक्षायें अपूर्ण रह जायेंगी। हमारे 36 प्रतिशत उत्तरदाता प्रशासनिक ढांचे की कमजोरी को एक बड़ी समस्या मानते हैं तथा अन्य 54 प्रतिशत इसको एक सीमा तक स्वीकारते हैं। केवल 10 प्रतिशत लोगों ने प्रशासनिक ढांचे की कमजोरी को कोई महत्व नहीं दिया।

निष्कर्ष

हमारे अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तराखण्डवासियों में यह एक व्यापक धारणा रही है कि एक बड़े प्रदेश का भाग होने के कारण और विधायकों की संख्या कम होने के कारण उत्तराखण्ड की उपेक्षा हुयी है और उसके विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। क्षेत्रवासियों को यह शिकायत भी रही है कि उत्तराखण्ड के लिये अपर्याप्त नियोजन धनराशि प्रदान की गयी और उसका सदुपयोग व्यापक भ्रष्टाचार व बाहर से आये हुये सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उदासीनता के कारण नहीं हो पाया। इस धारणा को व्यापक समर्थन मिला कि न तो इस क्षेत्र के लिये पर्याप्त संसाधन जुटाये गये और न ही विकास प्रक्रिया स्थानीय आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप हुई। उत्तराखण्डवासियों को इस बात से भी असंतोष हुआ कि क्षेत्र के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप न करके बाहरी क्षेत्रों के हित में किया जाता रहा।

विकास की अवैज्ञानिक और क्षेत्रपरक रणनीति के अभाव में और उसकी दोषपूर्ण क्रियान्वन प्रक्रिया के कारण क्षेत्र में व्यापक असंतोष उत्पन्न हुआ। उद्योगों के सीमित विकास और कृषि के पिछड़ेपन के कारण क्षेत्र में रोजगार के सम्यक् अवसर उपलब्ध न हो सके और बड़ी सख्या में क्षेत्र से युवाशक्ति का पलायन होता रहा। विकास प्रकिया से जनित इस असतोष को प्रसिद्ध समाजविद् डा0 पूरन चन्द्र जोशी निम्न स्वर में मुखरित करते हैं :

"पिछले कुछ समय से देख रहें हैं कि अल्पविकसित लेकिन समृद्ध संसाधनों वाले उत्तराखण्ड क्षेत्र में पूंजी,केन्द्रित, उच्च टेक्नालॉजी, ज्यादा कारोबार वाला आर्थिकतंत्र–कृषि, उद्योग, सेवा, परिवहन और संचार जैसे क्षेत्रों में छा रहा है। स्थानीय लोग इस अर्थतंत्र से काफी हद तक वंचित हैं क्योंकि उनके पास न तो वित्त और ऋण की व्यवस्था है, न ही बड़े उद्यम चलाने का अनुभव है, न संसाधन हैं, न ही अपनी शर्तों को लेकर मोल–भाव की क्षमता है। परिणामस्वरूप, बाहरी लोग निजी लाभ के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। उत्तराखण्ड में नये उद्यमों को ये ही लोग नियंत्रित कर रहें हैं जिनका न तो हिमालय क्षेत्र में सांस्कृतिक आधार है न ही उन्हें इस बात की कोई चिंता है कि इस नये अर्थतंत्र के पनपने से इस क्षेत्र की पारिस्थतिकी और पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है। हिमालय क्षेत्र में रोजी रोटी ओर रोजगार तथा आमलोगों की गुजारे की अर्थव्यवस्था के संकट से बड़े पैमाने पर जन शक्ति का पलायन हो रहा है। इस संकट पर अब अनेक अर्थशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों और नियोजकों का ध्यान गया है। लेकिन इस तथ्य की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है कि यह संकट दोहरी अर्थव्यवस्था, खास तौर पर आम लोगों की गुजारे की अर्थव्यवस्था के विपरीत 'सम्भ्रान्तों' की नयी अर्थव्यवस्था के पनपने से पैदा हुआ। इस नयी अर्थव्यवस्था को टिकाऊ क्षेत्रीय विकास और पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांतों के अनुरूप ढालना न केवल उत्तराखण्ड के लोगों के लिये वरन् पूरे देश के लिये बहुत बड़ी चुनौती है। यह चुनौती मात्र नियोजकों, नीति–निर्धारकों और राजनीतिज्ञों की ही नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों, समाज वैज्ञानिकों, सांस्कृतिक कार्यकत्ताओं और भारत के समस्त बुद्धिजीवियों की है क्योंकि उत्तराखण्ड की समस्या अब मात्र उत्तराखण्ड की नहीं, पूरे देश की हो गयी है।"

इस पृष्ठभूमि में यह भावना बलवती हुयी कि उत्तराखण्ड का पृथक राज्य बनने से लोगों को प्रशासन मिलेगा और विकास की सम्भावनाएं बढ़ेंगी। सामान्यतः इस बात का समर्थन किया गया कि न केवल उत्तर प्रदेश वरन् समस्त भारत को छोटे राज्यों के रूप में पुर्नगठन करना हितकर होगा।

हमारे सर्वेक्षण से यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि नब्बे के दशक के उत्तराखण्ड आन्दोलन ने एक जन आन्दोलन का रूप ले लिया था, जिसको सभी वर्गों का सक्रिय समर्थन प्राप्त था और सभी क्षेत्रों में आन्दोलन का व्यापक प्रभाव था। आन्दोलन का नेतृत्व विशेषकर छात्रों, बेराजगार नवयुवकों व भूतपूर्व सैनिकों द्वारा किया गया और महिलाओं की उसमें विशेष भागीदारी रही। साथ ही यह भी बात उभर कर आयी कि व्यापारी वर्ग तथा पिछड़ी और अनुसूचित जातियों का समर्थन अपेक्षाकृत कम था।

राजनीतिक दलों की भूमिका भी उत्तराखण्ड आन्दोलन मे गौण रही है। दीर्घकाल तक केन्द्र और राज्य मे सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी उत्तराखण्ड को पृथक राज्य बनाने के पक्ष में नही रही। अन्य राजनीतिक दल भी आन्दोलन के अंतिम चरणों में उसका व्यापक जनाधार देखते हुये और भविष्य में सत्ता में आने की दृष्टि से आन्दोलन से जुड़े। आन्दोलन को वास्तव में क्षेत्र से उभरे नैर्सगिक नेतृत्व ने, जिसमें युवा वर्ग और महिलायें अग्रणी थीं, सफलता की चोटी तक पहुंचाया।

उत्तराखण्ड आन्दोलन को विस्फोटक और क्षेत्र व्यापी रूप देने में जिस बात का प्रमुख योगदान था वह थी समाजवादी पार्टी सरकार की आरक्षण नीति की घोषणा, जो उत्तराखण्ड के सामाजिक परिवेश से कतई मेल नही खाती थी। हमारे सर्वेक्षण के आधे से अधिक लोग

आन्दोलन का मुख्य कारण सरकार की 1994 की आरक्षण नीति मानते हैं। जो सामाजिक वर्ग आरक्षण नीति से अधिक प्रभावित हुये, उनकी आन्दोलन में मुख्य भूमिका रही और जो वर्ग उससे अधिक प्रभावित नहीं हुयें या इस नीति से लाभान्वित हुये, उनका कम समर्थन आन्दोलन को प्राप्त हुआ। सरकार की दमन नीति, आन्दोलनकारियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाना व मुजफ्फरनगर काण्ड में हुयी ज़्यादातियों, विशेषकर महिलाओं पर, जैसी बातों ने आन्दोलन को एक भावनात्मक रूप देकर सहसा उभार दिया।

यदि आरक्षण नीति में प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखण्ड क्षेत्र के विशेष संदर्भ में संशोधन कर लिया जाता और आन्दोलन के प्रति दमनकारी नीति न अपना कर एक संवेदनशील राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाया जाता तो हमारी समझ में उत्तराखण्ड आन्दोलन इतना तूल न पकड़ता और सम्भवतः कई वर्षों तक पूर्व की भांति ही स्थिति बनी रहती और आन्दोलन वह स्वरूप न ले पाता जो 1994 के पश्चात् उसने लिया।

उत्तराखण्ड आन्दोलन को पिछले वर्षों की असंतुलित विकास प्रक्रिया से जनित व्यापक, क्षेत्रीय असंतोष के परिप्रेक्ष्य में देखना उचित होगा। जब आर्थिक पिछड़ापन और असंतुलित विकास प्रक्रिया जनित असंतोष ऐसे क्षेत्र में उभरता है जिसकी एक पृथक भौगोलिक, सांस्कृतिक व भाषाई अथवा अनुवांशिक पहचान है, तो वह एक क्षेत्रीय आन्दोलन का रूप ले लेता है। यदि इस आन्दोलन को एक परिपक्व राजनैतिक एवं संवेदनशील तरीके से अभिमुख नहीं किया जाता है, तो यह एक पृथक राज्य या कुछ परिस्थितियों में अलागववादी स्वरूप ले लेता है।

आज देश के विभिन्न अंचलों से विकास प्रक्रिया के स्वरूप को बदलने और उसको जन मानस की आकांक्षाओं के अनुरूप ढालने के लिये सत्ता के विकेन्द्रीकरण और वर्तमान राजनैतिक ढांचे को बदलने और राज्यों के पुर्नगठन की मांग कही मन्द स्वरों में और कहीं मुखर स्वरों में उठ रही है। उत्तराखण्ड आन्दोलन भी इन्हीं राजनीतिक और सामाजार्थिक प्रक्रियाओं का एक उदाहरण है, जिसको अपने उद्देश्य में पहुंचने में अपेक्षाकृत शीघ्र सफलता मिली। लेकिन क्या एक पृथक उत्तरांचल राज्य बन जाने से ही जन मानस की यह अपेक्षायें पूर्ण हो जायेगी ? इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि नये राज्य में वास्तविक सत्ता किस वर्ग के हाथ में आती है और क्या वहां वास्तव में विकास की प्रक्रिया में मूलभूत बदलाव आता है जो सामान्य नागरिकों की आशा के अनुरूप हो। समय ही इस बात का उत्तर दे पायेगा।

संदर्भ सूची

आर० एस० बोरा (1996), **"हिमालय माइग्रेशन : ए स्टडी ऑफ द हिल रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश"**, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

के० एस० बल्दिया (1988), **"कुमायूं : लैण्ड एण्ड पीपल"**, ज्ञानोदय प्रकाशन, नैनीताल

के० एस० बल्दिया (1996), **"डिस्टिक्ट सोसियो-क्लचरल आईडेण्टिटी, प्रोफाईल ऑफ रिर्सोसेज एण्ड प्लानिंग फॉर डवलपमेंट ऑफ उत्तराखण्ड"**, वल्दिया (1996) में सम्मिलित।

के० एस० बल्दिया (सम्पादित) (1996), **"उत्तराखण्ड आज"**, श्री अल्मोड़ा बुक डिपो, अल्मोड़ा

जी० एस० पाण्डे (1997) **"ए डवलपमेंट एक्सपीरियन्स एण्ड आपशन्स इन ए हिल रीजन : दी केस ऑफ उत्तराखण्ड"**, यू० पी० इण्डिया, इण्टरनेशनल सेन्टर फॉर इन्टीग्रेटिड माउन्टेन डवलपमेंट, काठमाण्डू।

पूरन चन्द्र जोशी, (1994) **"भारतीय नवजागरण और उत्तराखण्ड"** सुरेश नौटियाल (सम्पादित) 1994 में सम्मिलित।

बी० आर० पंत (1994), **"उत्तराखण्ड का प्राकृतिक आधार"**, नौटियाल (सम्पादित), 1994 में सम्मिलित

बी० डी० पाण्डे (1996), **"ब्वाई उत्तराखण्ड"**, वल्दिया (सम्पादित), 1996 में सम्मिलित।

नौटियाल (संपादक)(1994), **"उत्तराखण्ड : एक अध्ययन, आंकलन और प्रस्ताव (भौगोलिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक संदर्भ में)"**, धाद, देहरादून।

परिशिष्ट
उत्तरदाताओं की सूची

कुमायूं मण्डल

1. श्री वी० एस० रावत, वकील, भिकियासैंण, अल्मोड़ा
2. श्री आर० के० पन्त, अध्यक्ष, भारतीय युवा मोर्चा, अल्मोड़ा
3. श्री पी० एस० डंगवाल, भू० पू० अध्यक्ष, यू० के० डी०, रानीखेत, अल्मोड़ा
4. श्री एच० डी० बहुगुणा, महासचिव, यू०के०डी०, देघाट, अल्मोड़ा
5. डा० एच० सी० जोशी, सचिव, उत्तराखण्ड कलाकार संघ, अल्मोड़ा
6. डा० विद्याधर सिंह नेगी, भिकियासैण, अल्मोड़ा
7. श्री कौशल सक्सेना, वकील, नरसिंगवाडी, अल्मोड़ा
8. श्री हरीशचन्द्र, नवल गाव, स्याल्दे, अल्मोड़ा
9. श्री जे० एस० बिष्ट, भूतपूर्व एम० एल०ए०, यू०के०डी०, रानीखेत, अल्मोड़ा
10. श्री आजाद सिंह भैर्याल, प्रधानाचार्य, इण्टर कालेज, रनेती, अल्मोड़ा
11. श्री बिशन सिंह गढिया, ज्येष्ठ प्रमुख, कपकोट, बागेश्वर
12. श्री रमेश पाण्डे, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड वन पंचायत संघर्ष समिति, कपकोट, बागेश्वर
13. श्री सुरेश चन्द्र मिश्रा, प्रधानाचार्य, इण्टर कालेज, सौंग, बागेश्वर
14. श्री जे० एस० रौतेला, वकील, भूतपूर्व उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड संघर्ष वाहिनी, अल्मोड़ा
15. श्री गंगा सिंह पांगती, सामाजिक कार्यकर्ता, कपकोट, बागेश्वर
16. श्री एच० एस० डेक, भूतपूर्व सैनिक, लोहाघाट, अल्मोड़ा
17. डा० गणेश मिश्रा, डी० लिट स्कालर, हल्द्वानी, नैनीताल
18. श्री ए० के० अग्रवाल, महासचिव, राष्ट्रीय कांग्रेस, रामनगर, नैनीताल
19. श्री राजीव लोचन शाह, पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्त्ता, नैनीताल
20. श्री सतीश गड़कोटी, वकील, लोहाघाट, चम्पावत
21. श्री टी० डी० पाण्डे, भूतपूर्व अभियन्ता व अध्यक्ष, लोक चेतना मंच, रानीबाग, नैनीताल
22. डा० पी० जोशी, चिटगाल गांव, पिथौरागढ
23. डा० जी० सी० पन्त, पिथौरागढ़
24. डा० एम० सी० भट्ट, उपाध्यक्ष उत्तराखण्ड शोध संस्थान और शिक्षक संघ, पिथौरागढ़
25. श्री आर० एस० चौहान, वकील, डीडीहाट, पिथौरागढ़
26. श्री एल० पी० गहतोड़ी, प्रधानाचार्य उदयराज सिंह हिन्दू इण्टर कालेज, काशीपुर, उधमसिंह नगर
27. डा० आर० सी० पन्त, अधिष्ठाता, विज्ञान व मानविकी, कृषि विश्व विद्यालय, पन्तनगर
28. श्री एन० डी० जोशी, जिला संयोजक यू०के०डी०, पन्तनगर, उधमसिंह नगर
29. डा० आई० राम, प्रधानाचार्य, पी० जी० कालेज, खटीमा, उधमसिंह नगर

गढ़वाल मण्डल

1. श्री के० एस० फोनिया, भू० पू० मंत्री और वर्तमान एम० एल०ए० उत्तरांचल, चमोली
2. श्री के० डी० कन्याल, भू०पू० प्रधानाचार्य, महासचिव समाजवादी पार्टी और पी० टी० आई० जिला प्रतिनिधि,घाट, चमोली
3. श्री वी० एस० बुटोला, प्रवक्ता, राजकीय इण्टर कालेज गैरसैण, चमोली
4. श्री डी० पी० उनियाल, सदस्य, सी० पी० आई०, देहरादून
5. श्री के० एस० नेगी, पद्मश्री, पद्मभूषण, ब्रेल विशेषज्ञ, देहरादून
6. श्रीमती सुशीला वलूनी, उपाध्यक्ष, यू०के०डी०, देहरादून
7. डा० डी० एम० जोशी, रसायन शास्त्र विभाग, एच० एन० बहुगुणा विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल
8. श्री टी० सी० भट्ट, कार्यकारिणी सदस्य, यू०के०डी०, ज्वालापुर, देहरादून
9. श्री सुभाष बन्सल, पत्रकार, दुगड्डा पौड़ी, गढवाल
10. श्री वी० वी० कुकरेती, सदस्य, स्वयं सेवी संस्था, मुन्नी की रेती, टेहरी गढ़वाल
11. श्री जोत सिंह वग्याल, टेहरी गढ़वाल
12. श्रीमती कौशल्या रानी, सदस्य युवा कांग्रेस, सम्पादक –हिम प्रवक्ता, नरेन्द्र नगर, टेहरी गढवाल
13. श्री महावीर उनियाल, वकील, न्यू टेहरी गढवाल
14. डा० पी० एस० मखलोगा, रसायन शास्त्र विभाग, पी० जी० कालेज उत्तरकाशी, उत्तरकाशी
15. श्री वी० एस० कुमाई, सी० पी० आई० राज्य कमेटी सदस्य, मसूरी, देहरादून
16. श्री के० एस० रावत, वकील, जिला अध्यक्ष बी० जे० पी०, उत्तरकाशी
17. श्री एस० सी० रावत, सदस्य, कांग्रेस कमेटी, नवगांव, उतरकाशी
18. श्री एन० डी० जगूड़ी, महासचिव कांग्रेस, उत्तरकाशी
19. डा० आर० के० उप्पान, विभागाध्यक्ष कामर्स, पी० जी० कालेज, उत्तरकाशी
20. श्री पी० एन० नौटियाल, भौतिक विज्ञान विभाग, पी० जी० कालेज, उत्तरकाशी
21. श्री के० एस० रावत, भू० पू० कांग्रेस महासचिव, उत्तरकाशी